वर्ष 13 • अंक 43 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 10 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 3

कॉग्निजेंट ने वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान लिया वापस

सुरेश नारायणन ▶▶ पृष्ठ 2

संकट के बाद नए दौर से जूझेगा उद्योग

डॉलर रु. 76.30 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 82.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु. 45020 ▲ 310 रुपये | सेंसेक्स 31159.60 ▲ 1265.70 | निफ्टी 9111.90 ▲ 363.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 9086.70 ▼ 25.20 | ब्रेंट क्रूड 28.40 डॉलर ▲ 0.60 डॉलर

अर्थव्यवस्था पर कोविड साया

आरबीआई ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट में देश की आर्थिक हालत को लेकर जताई चिंता

बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 अप्रैल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी देश की अर्थव्यवस्था पर काले साये की तरह मंडरा रही है और इसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में यह चेतावनी दी।

आरबीआई का कहना है कि यह महामारी ऐसे वक्त अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है जब वह पटरी पर लौटनी शुरू हुई थी, लेकिन अब कोविड-19 की काली छाया इसके भविष्य पर मंडरा रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इससे देश में आर्थिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक व्यापार और वृद्धि में भारी मंदी के कारण भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर और गहरा असर होगा।

आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा कि घरेलू वित्तीय बाजारों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों से अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने में मदद मिलेगी जिसकी शुरुआत 2018-19 की पहली तिमाही में हुई थी और जो 2019-20 की दूसरी छमाही में भी जारी रही। कोविड-19 संकट से पहले 2020-21 का परिदृश्य बेहतर दिख रहा था। रबी की बंपर पैदावार हुई थी और 2019-20 के दौरान खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत ग्रामीण मांग में मजबूती के अनुकूल थीं। नीतिगत दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया था और खपत तथा निवेश मांग के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट कर की दर में कटौती और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के लिए किए गए उपाय तथा बुनियादी ढांचे पर खर्च का घरेलू मांग पर सकारात्मक प्रभाव होना था। लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।

आरबीआई का कहना है कि कोविड-19 के बाद के अनुमानों के मुताबिक 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। अलबत्ता अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में तेज गिरावट आती है तो यह भारत के लिए बेहतर स्थिति हो सकती है। हालांकि बैंक का साथ ही कहना है कि इससे हुए फायदे से लॉकडाउन और बाहरी मांग में कमी से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है।

अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाने वाले पेशेवरों के बीच मार्च में लॉकडाउन की घोषणा से पहले कराए गए एक सर्वेक्षण में उम्मीद की गई थी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2020.21 की चौथी तिमाही में बढ़कर 6.1 प्रतिशत रह सकती है, जो 2019-20 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत रही थी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक अप्रैल के पहले हफ्ते में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए इसे मार्च में ही संपन्न कर दिया गया था। समिति का कहना है कि इस महामारी के कारण पैदा हुए व्यापक आर्थिक जोखिम बेहद गंभीर हो सकते हैं और मांग तथा आपूर्ति पर गहरा असर डाल सकते हैं।

समिति ने इस महामारी से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हरसंभव उपाय करने पर जोर दिया। समिति ने नीतिगत रीपो दर में 75 आधार अंक की कमी के साथ कई तरह के उपायों की घोषणा की थी। इनमें अर्थव्यवस्था में क्रेडिट प्रवाह बेहतर करने के लिए नकदी बढ़ाने के उपाय और ऋण के भुगतान में राहत देना शामिल था।

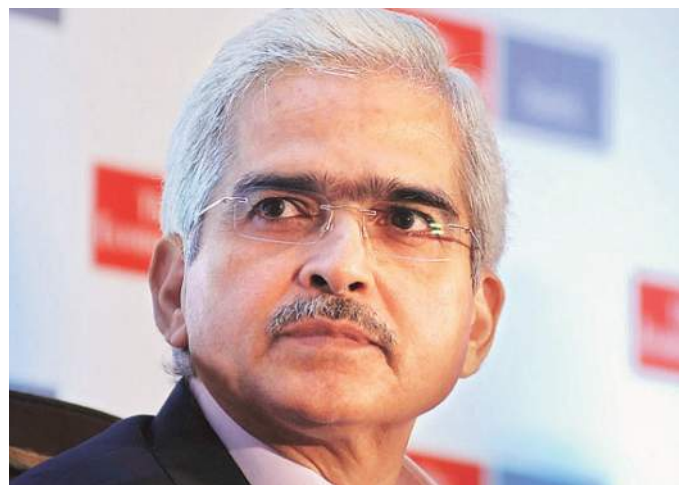

- लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित होंगी आर्थिक गतिविधियां
- कोविड संकट से पहले पटरी पर लौट रही थी अर्थव्यवस्था
- मंदी में जा सकती है वैश्विक अर्थव्यवस्था
- मुद्रास्फीति के मौजूदा स्थिति में बने रहने का अनुमान

डेट योजनाओं का सबसे बुरा प्रदर्शन

जश कृपलानी
मुंबई, 9 अप्रैल

- फंड उद्योग का बाजार 18 प्रशितत कम होकर रह गया 22.27 लाख करोड़
- आर्बिट्राज योजनाओं से 33,000 करोड़ रुपये से अधिक निकासी
- शेयर परिसंपत्तियां ढाई साल के निचले स्तर पर
- वित्त वर्ष 2020 में एसआईपी प्रवाह 1 लाख करोड़ रुपये के पार

म्युचुअल फंड (एमएफ) उद्योग के लिए मार्च अच्छा नहीं रहा। इस दौरान डेट योजनाओं से से 1.9 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई। यह किसी भी वर्ष के अंत में डेट योजनाओं से निकाली गई सबसे अधिक राशि है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा बिकवाली से प्रतिफ ल में कमी और कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन से नकदी बचाने के लिए कॉरपोरेट ट्रेजरी निकासी के दबाव से यह स्थिति नौबत आई।

डेट की सभी श्रेणियों में शुद्ध निकासी देखने को मिली और तरल (लिक्विड) योजनाओं से 1.1 लाख करोड़ रुपये निकाले गए। ड्यूरेशन फंडों में भी अच्छी खासी निकासी देखने को मिली। कॉर्पोरेट और संस्थागत निवेशक अपने फंडों को इन्हीं में निवेश करते हैं। बेहद कम अवधि के ड्यूरेशन फंडों में मार्च में 29,000 करोड़ रुपये की निकासी की गई। इसी तरह कम अवधि के ड्यूरेशन फंडों से पिछले महीने 19,921 करोड़ रुपये की निकासी हुई। ये फंडों 6 से 12 महीने की डेट प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

प्रतिफल में तेजी से डेट स्कीमों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों का मार्क टू मार्केट मूल्यांकन प्रभावित हुआ। एफआईआई द्वारा मार्च में की गई भारी बिकवाली से नकदी संकट पैदा हुआ, जिससे लिक्विड स्कीमें बुरी तरह प्रभावित हुई और उनमें नकारात्मक प्रतिफल देखने को मिला।

सुंदरम एमएफ के प्रबंध निदेशक सुनील सुब्रमण्यन ने कहाए यह लिक्विड योजनाओं का असामान्य प्रदर्शन था, जिसने निवेशकों को भी चौंका दिया था। एक साल तक की परिपक्वता अवधि की प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले मनी मार्केट फंडों में 27,402 करोड़ रुपये की निकासी देखने को मिली।

एसबीआई एमएफके कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य विपणन अधिकारी डीपी सिंह ने कहाए वित्त वर्ष के समाप्त होने के कारण डेट स्कीमों में रिडम्शन देखने को मिला। कॉरपोरेट ट्रेजरी भी लॉकडाउन की स्थिति के लिए नकदी बचाना चाहती थीं जिससे निवेशकों ने भारी निकासी की। मार्च में दूसरी डेट श्रेणियों में भी भारी निकासी देखने को मिली। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग तथा पीएसयू फंड में निवेशकों की परिसंपत्तियों में लगातार दसवें महीने तक वृद्धि के बाद गिरावट देखने को मिली।

मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट में निदेशक, फंड रिसर्च, कौस्तुभ बेलापुरकर ने कहा कि दोनों श्रेणियों में भारी निकासी देखने को मिली क्योंकि निवेशक सितंबर 2018 में आईएलऐंडएफएस संकट के बाद प्रतिफल के बजाय सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे, जिससे क्रेडिट बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बन गई।

वित्त वर्ष 2020 में क्रेडिट रिस्क फंडों में सबसे अधिक निकासी देखने को मिली। निवेशकों ने इन फंडों से कुल 5,568 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की।

एक नज़र

गुड फ्राईडे पर आज बंद रहेंगे बाजार

शुक्रवार को गुड फ्राईडे के अवसर पर बाजार में कारोबार नहीं होगा। शेयर सहित मुद्रा और जिंस बाजार सभी बंद रहेंगे। यह सप्ताह कारोबार के लिहाज से छोटा रहा और केवल चार दिन ही कारोबार हुआ।

फरवरी में बढ़ी औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर

खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश के औद्योगिक उत्पादन में इस साल फरवरी में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकडों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इससे पहले फरवरी 2019 में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकडों के अनुसार विनिर्माण उत्पादन इस साल फरवरी में 3.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। बिजली उत्पादन आलोच्य महीने में 8.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि फरवरी 2019 में इसमें 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी के दौरान आईआईपी वृद्धि दर घटकर 0.9 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2018-19 की समान अवधि में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1930 के बाद आर्थिक वृद्धि दर होगी सबसे कम

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जियोरजीवा ने गुरुवार को कहा है कि 1930 की वैश्विक मंदी के बाद वर्ष 2020 में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कमजोर रह सकती है। जियोरजीवा ने कहा कि दुनिया के 170 से अधिक देशों के लिए मौजूदा वर्ष वैश्विक मंदी के बाद सबसे भारी गुजरेगा। उन्होंने वाशिंगटन में अगले सप्ताह आईएमएफ की सालाना बैठक से पहले एक कार्यक्रम 'कन्फ्रंटिंग द क्राइसिस: प्रायोरिटीज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी' में यह आशंका जताई।

फेडरल रिजर्व देगा 2.3 लाख डॉलर अतिरिक्त रकम

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कोरोनावायरस संकट के बाद मचे भूचाल से देश की अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए अतिरिक्त 2.3 लाख करोड़ डॉलर की रकम मुहैया करने की घोषणा की है। छोटे कारोबारों और नगर निगमों को ऋण सुविधा मुहैया कराने और कंपनियों के बॉन्ड बाजार का दायरा बढ़ाने के लिए फेडरल रिजर्व नए माध्यमों का इस्तेमाल करेगा। केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जे पॉवेल ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा संकट में सार्वजनिक स्वास्थ्य को पुख्ता करना हमारे देश की प्रमुख प्राथमिकता है। इस बीच, लगातार तीसरे सप्ताह अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते का दावा करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। तीसरे सप्ताह में कुल 66 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किए।

कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपये कोष

सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने और भविष्य में बीमारी के प्रकोपों से बचाव की तैयारी के लिए 15,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की है। गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस कोष में 7,774 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तात्कालिक जरूरत पूरी करने में किया जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार शेष राशि का उपयोग एक से चार साल तक की अवधि में किया जाएगा। पृष्ठ 8

डॉक्टरों से दुर्व्यवहार नहीं होगा बर्दाश्त

भाषा
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी से जूझने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफदरजंग अस्पताल की दो महिला रेजीडेंट डॉक्टरों पर हमला किए जाने की घटना के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने यह चेतावनी दी है।

इन रेजीडेंट डॉक्टरों के बारे में यह अफवाह फैलाई गई थी कि वे गौतम नगर इलाके में कोरोनावायरस का संक्रमण फैला रहीं हैं। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'राज्य सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों के संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 21 इलाकों की पहचान ऐसे क्षेत्र के रूप में की गई है, जहां संक्रमण के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों को इन इलाकों में प्रवेश करने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा, 'वह जानते हैं कि लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन वायरस को फैलने से रोकने भी जरूरी है।'

उम्मीद पर उछला बाजार

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 9 अप्रैल

- गुरुवार को बाजार में दर्ज हुई 4 प्रतिशत उछाल
- सप्ताह 13 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ बाजार

घरेलू शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी गई और सूचकांक 4 प्रतिशत बढ़त पर बंद हुए। इस हफ्ते कुल मिलाकर बाजार 13 प्रतिशत फायदे में रहा। दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की खबरों, तेल उत्पादन में कटौती को लेकर प्रमुख तेल उत्पादक देशों के बीच बातचीत और कई देशों में कोविड-19 का प्रसार अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद से निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। विदेशी निवेशकों ने लगातार तीसरे दिन लिवाली की। आज उन्होंने 1,738 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और तीन में कुल 4,200 करोड़ रुपये की लिवाली की।

सेंसेक्स 1,266 अंक चढ़कर 31,160 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 363 अंक की तेजी के साथ 9,112 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक 23 मार्च के अपने निचले स्तर से करीब 20 फीसदी चढ़ चुके हैं। खबरों के अनुसार सरकार एसएमई की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने पर विचार कर रही है। पिछले महीने सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, जिसमें कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा और नकद अंतरण भी शामिल हैं।

मारसेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'तेल कीमतों में आगे और कमी से सरकार का राजकोषीय दबाव थोड़ा कम होगा और सरकार उस रकम का इस्तेमाल कुछ और प्रोत्साहन उपायों में कर सकती है।' आने वाले दिनों में लॉकडाउन के सकारात्मक असर की उम्मीद से भी निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। हालांकि बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि कई क्षेत्रों के शेयरों का मूल्यांकन अभी वाजिब स्तर पर है और निवेशकों को सलाह है कि वे शेयरों की खरीद कर अपने बहीखाते को मजबूत बनाएं।

त्यापार गोष्ठी

कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरु हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthti@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या कोविड-19 संकट के बाद जल्द उबर पाएगी देश की अर्थव्यवस्था

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अर्थव्यवस्था अधिक दिनों तक लॉकडाउन झेलेन में है सक्षम	हां	44.44%
	नहीं	55.56%

प्रवासी श्रमिकों का ब्योरा जुटा रही सरकार

सोमेश झा
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने देश भर फैले राहत शिविरों या नियोक्ता के परिसरों या क्लस्टरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों का खाका तैयार करने की व्यापक कवायद शुरू की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकार ऐसे लाखों श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना चाहती है ताकि उनके लिए समुचित राहत पैकेज की घोषणा की जा सके। असल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के वास्ते किए गए लॉकडाउन से समाज में सर्वाधिक प्रभावित यह वर्ग हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मुख्य श्रम आयुक्त के साथ समन्वय करने और 11 अप्रैल तक प्रवासी श्रमिकों का समग्र डेटा मुहैया कराने को कहा है।

मुख्य श्रम आयुक्त रंजन वर्मा ने 8 अप्रैल को अपने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है, 'जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन से काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए तीन दिन के अंदर प्रवासी मजदूरों का डेटा उपलब्ध कराना तत्काल आवश्यक है।'

डेटा का संग्रह तीन मुख्य स्रोतों से किया जाएगा : राहत शिविरों या आश्रय स्थल (जिलावार), नियोक्ता के परिसरों जहां प्रवासी श्रमिक रह रहे हैं और स्थनीय इलाकों जहां आमतौर पर ऐसे श्रमिक-मजदूर रहते हैं। गैर-सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट की ओर से संचालित राहत शिविरों में रहने वाले श्रमिकों के भी डेटा लिए जाएंगे।

डेटाबेस से पता चलेगा कि प्रवासी श्रमिकों के पास बैंक खाता है या नहीं या प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खुला है कि नही। इसके अलावा यह भी जानकारी होगी कि श्रमिकों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर का लाभ मिला है या नहीं। इसके साथ ही श्रमिकों के आधार क्रमांक भी लिए जाएंगे। डेटा को उनके काम के आधार पर भी अलग किया जाएगा। ■ शेष पृष्ठ 8

फोटोः संजय शर्मा

लॉकडाउन के बाद पैदल गांव पहुंचे कामगार	5-6 लाख
राहत शिविरों में लोगों की संख्या	10.03 लाख
नियोक्ताओं से आश्रय या भोजन पाने वाले	15 लाख
सरकार और एनजीओ से भोजन पाने वाले	84 लाख
कुल आश्रय गृहों की संख्या	22,567

स्रोतः उच्चतम न्यायालय में दाखिल सरकार की रिपोर्ट

कोरोना मामले

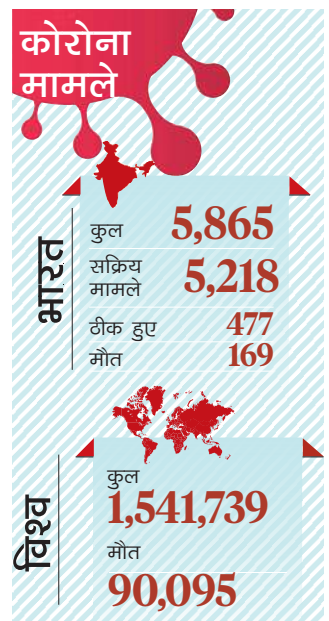

नोटः कुल मामलों में एक पलायन किया मरीज भी शामिल है।
स्रोतः स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉन हॉपकिंस रिसोर्सेस सेंटर

श्रम संगठनों से मांगा सहयोग

राष्ट्रीय राजधानी के कारखानों और गोदामों में काम करने और जरूरी वस्तुओं के परिवहन एवं वितरण के लिए कामगारों का इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक संगठनों से सहयोग करने का कहा है। देश भर में लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाए जाने की आशंका है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें कुछ औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू करने केलिए जूझ रही हैं क्योंकि देश के शहरों, कस्बों और गांवों में जरूरी वस्तुओं के स्टॉक फिर से तैयार करने की जरूरत है।

राज्य सरकारों का कहना है कि शहर के कारखानों और गोदामों में काम करने के लिए पर्याप्त कामगार नहीं हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश के विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से दिल्ली जैसे शहरों से भारी तादाद में दूसरे राज्यों के कामगार अपने गांव-कस्बों की ओर वापस चले गए। ■ पृष्ठ 8

खबरों में रहे स्टॉक

हिंदुस्तान यूनिलीवर

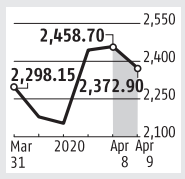

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 2,458.70 पिछला बंद भाव
₹ 2,372.90 आज का बंद भाव

▼ 3.49 %

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

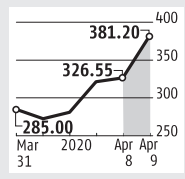

क्रिसिल ने ऋण एवं बैंक सुविधा पर रेटिंग बरकरार रखी

₹ 326.55 पिछला बंद भाव
₹ 381.20 आज का बंद भाव

▲ 16.74 %

टाइटन कंपनी

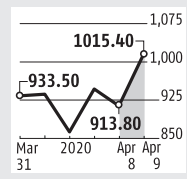

राजस्व एवं आय की लंबी अवधि का परिदृश्य आकर्षक

₹ 913.80 पिछला बंद भाव
₹ 1,015.40 आज का बंद भाव

▲ 11.12 %

बजाज फाइनैंस

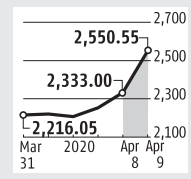

बाजार पूंजीकरण दोबारा 1.53 लाख करोड़ रुपये हुआ

₹ 2,333.00 पिछला बंद भाव
₹ 2,550.55 आज का बंद भाव

▲ 9.32 %

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज

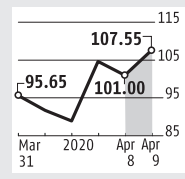

एलेरिस अधिग्रहण के लिए नोवेलिस को मिली अंतिम मंजूरी

₹ 101.00 पिछला बंद भाव
₹ 107.55 आज का बंद भाव

▲ 6.49 %

संक्षेप में

जेएसपीएल की प्रवर्तक फर्मों ने लौटाया कर्ज

जिंदल स्टील ऐंड पावर लि. (जेएसपीएल) की तीन प्रवर्तक कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों का 391 करोड़ रुपये कर्ज लौटाया है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये कंपनियां हैं ओपेलिना सस्टेनेबल सर्विसेज लि., ओपीजे ट्रेडिंग प्राइवेट लि. और गगन इन्फ्रा एनर्जी। अधिकारी ने कहा, इन प्रवर्तक कंपनियों ने तीन दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 747 करोड़ रुपये के कर्ज में से करीब 391 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। *भाषा*

रिपोर्ट जमा कराने के लिए ब्रोकरों को मिली मोहलत

एनएसई ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर ग्राहक वित्त पोषण और कुल परिसंपत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित रिपोर्ट जमा करने के लिए ब्रोकरों को नियमों में छूट देते हुए अधिक समय दिया है। एनएसई ने हालांकि एक परिपत्र में कहा कि साइबर हमलों और अन्य खतरों से संबंधित घटनाओं पर तिमाही रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। एनएसई ने ब्रोकरों को ग्राहक वित्त पोषण, कृत्रिम बौद्धिकता और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों और तिमाही अनुपालन प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। अनुपालन प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल थी। *भाषा*

उत्पादन की अनुमति चाहें कंपनियां

प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कम से कम निर्यात के लिए उत्पादन की मंजूरी की दरकार

सुरजीत दास गुप्ता और टीई नरसिम्हन
नई दिल्ली/चेन्नई, 9 अप्रैल

- बजाज ऑटो ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि केवल निर्यात के लिए उत्पादन की मंजूरी दी जाए
- तिरुपुर में कपड़ा निर्यातकों को चिंता सता रही है कि कहीं उन्हें 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर न गंवाना पड़ जाए
- कंपनियां 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ भी उत्पादन के लिए तैयार

विनिर्माण क्षेत्र की ये ऐसी कंपनियां हैं जो दो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से परिचालन करती हैं लेकिन पूरी तरह अलग-अलग क्षेत्रों में। तिरुपुर औद्योगिक केंद्र में कपड़ा क्षेत्र की कंपनियां काम करती हैं जबकि पुणे के समीप चाकण में वाहन कंपनियों में बजाज, फोक्सवैगन ग्रुप, डेमलर और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कारोबार में अंतर होने के बावजूद राज्य सरकार से उनकी मांग समान है: भले ही चरणबद्ध तरीके से लेकिन उन्हें अपनी फैक्टरी खोलने की अनुमति दी जाए ताकि वे भारी नुकसान से बच सकें।

देश के प्रमुख कपड़ा केंद्र तिरुपुर में कपड़ा निर्यातकों को चिंता सता रही है कि कहीं उन्हें 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर न गंवाना पड़ जाए। उन्हें अप्रैल और मई के दौरान यूरोप और अमेरिका में अपने ग्राहकों को नमूना उत्पाद भेजना जरूरी होता है। उन्हीं नमूनों के आधार पर अगली गर्मियों या सर्दियों के लिए पर्याप्त ऑर्डर मिलते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर चीन और बांग्लादेश के निर्यातक हथिया लेंगे क्योंकि उनकी फैक्टरियां लगातार परिचालन में हैं।

तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष राजा एम षणमुगम ने कहा, 'कंपनियों ने कहा है कि वे 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ भी नमूनों का उत्पादन कर लेंगी। यदि वे इस महीने नमूनों की आपूर्ति नहीं कर पाईं तो अगले महीने ऑर्डर चीन चले जाएंगे जो विनिर्माण पहले ही शुरू कर चुका है। इसके अलावा कुछ ऑर्डर बांग्लादेश भी जा सकते हैं जहां पिछले रविवार से आंशिक तौर पर उत्पादन शुरू हो चुका है।'

अधिकतर निर्यातकों के पास आवश्यक श्रम बल उपलब्ध है और उन्होंने कच्चे माल की सोर्सिंग लॉकडाउन से पहले ही कर चुके हैं। अब उन्हें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को लागू करते हुए नमूनों के उत्पादन के लिए अनुमति मिलने की आवश्यकता है।

चाकण में कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जो लॉकडाउन में आंशिक ढील पर जोर दे रही हैं। उदाहरण के लिए बजाज ऑटो अपने आधे से अधिक दोपहिया वाहनों का निर्यात करती है। उसने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि केवल निर्यात के लिए उत्पादन की मंजूरी दी जाए। कंपनी के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने कहा, 'हमने कम से कम निर्यात के लिए उत्पादन शुरू करने की मंजूरी मांगी है ताकि भारतीय उद्योग और इसकी आपूर्ति शृंखला की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए।'

चाकण में मौजूद कुछ कार विनिर्माताओं के सूत्रों ने कहा कि वे कुछ रियायत देने पर जोर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने वाहनों के डिस्पैच के लिए अनुमति मांगी है ताकि फैक्टरी परिसर से वाहनों को डीलरों तक पहुंचाया जा सके। कुछ कंपनियां सीमित उत्पादन की मांग कर रही हैं। एक कार विनिर्माता ने कहा, 'मेरे हिसाब से इस तरह के संयंत्रों को परिचालन की अनुमति दी जानी चाहिए और नियोक्ता को सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग, मास्क एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।'

संकट के बाद नए दौर से जूझेगा उद्योग: नेस्ले

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार के कारण जारी मौजूदा संकट पूरे कारोबारी माहौल को बदल देगा। जब यह संकट समाप्त हो जाएगा तो उद्योग नए दौर का सामना करेगा, जिसमें हर चीज के एक नए मानक होंगे।

दफ्तर से दूर रहकर काम करने जैसे बदलाव और विनिर्माण संयंत्रों में स्वच्छता के सख्त मानक अपनाने के अलावा यह संकट ब्रांडों की तरफ से ग्राहकों को दिए जाने वाले संदेश को सदा के लिए बदल सकता है।

नारायणन ने कहा, ब्रांडों के अभियान की बात करें तो विज्ञापन अब घर में उपभोग वाले पलों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो पहले घर से बाहर के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता रहा है। काम करने के तरीके भी इजाद हो सकते हैं, जैसा कि लॉकडाउन की लंबी अवधि में घर से काम करने के दौरान इच्छित नतीजे से जुड़ी कई चीजें बिखर गई है।

लॉकडाउन के दौरान जिन विनिर्माताओं को काम करने की अनुमति मिली है उनमें नेस्ले इंडिया शामिल है और कंपनी ने अपने कर्मियों को सुरक्षित रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। फर्म अपनी बिक्री टीम को प्रोटेक्शन कवर देने की तैयारी कर रही है, जो वितरक साझेदार के लिए काम करते हैं और राज्य कर्मचारी बीमा कार्यक्रम के दायरे में नहीं आते। कंपनी ने उनके लिए तीन महीने का कोविड-19 बीमा सुरक्षा देने की योजना बनाई है। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मार्च का 100 फीसदी सेल्स इंसेटिव दिया है।

नारायणन ने कहा, अपनी फैक्टरी में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया है और अन्य एहतियाती कदम भी उठाए हैं ताकि कर्मियों व उनके करीबी का स्वास्थ्य ठीक रहे। हमने परिचालन वाली हर फैक्टरी में एक कार्यक्रम चलाया है जो तय समय में काम करने के लिए हर ऑपरेटरों को इनाम देगा।

चूंकि ज्यादातर कर्मी घर से काम कर रहे हैं और तकनीक ने रोजाना की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है, हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं। घर से काम करने जैसे नए तरीके से दबाव, डर और व्यग्रता देखने को मिली है और इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ।

फर्म ने हालांकि नई नियुक्तियों पर अभी फैसला नहीं लिया है। कंपनी पहले से ही समर इंटर्न के लिए कार्यक्रम का संचालन कर रही है। नारायणन ने हालांकि संभावित छंटनी और वेतन कटौती पर टिप्पणी नहीं की। नेस्ले इंडिया के भारत में 7,000 प्रत्यक्ष कर्मी हैं और शेयर बाजार में अब तक कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बिक्री नुकसान के बावजूद बीएसई पर उसका शेयर लॉकडाउन से अब तक 30 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है जबकि एफएमसीजी इंडेक्स में 25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

लॉजिस्टिक कंपनियों की बढ़ी चुनौती

कोरोनावायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति दी है। लेकिन लॉजिस्टिक कंपनियों को माल ढुलाई करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रक ड्राइवर हुए हैं जिन्हें अधिकारियों की झिड़की सहने के अलावा अपने गांव में भी लोगों के गलत वर्ताव से जूझना पड़ता है। छोटे-मोटे कारोबार को भी तगड़ा झटका लगा है। गुड़गांव की लॉजिस्टिक्स फर्म रिविगो के सह-संस्थापक गजल कालरा ने कहा, 'जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो हमारे पांच ट्रक ट्रांजिट में थे। उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही सीमाओं पर उन्हें रोक दिया गया। उन्हें राज्यों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सेब जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप वह पूरी खेप बेकार हो गई। *बीएस*

मैरिको और जीसीपीएल के राजस्व में आएगी गिरावट

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 9 अप्रैल

उपभोक्ता वस्तु दिग्गजों मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर (जीसीपीएल) ने अपने ताजा तिमाही व्योरे में कहा है कि कोविड-19 महामारी और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से जनवरी-मार्च अवधि में उन्हें भारी राजस्व गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मैरिको ने यह भी कहा है कि वह सफोला के तहत खाद्य तेल और उत्पादों में शानदार बिक्री की वजह से मार्च तिमाही के एबिटा में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करेगी। हालांकि बिक्री के संदर्भ में उसकी अन्य श्रेणियों का प्रदर्शन सुस्त रहा है।

मैरिको और जीसीपीएल ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों की औपचारिक घोषणा से पहले जनवरी-मार्च के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन का संकेत दिया है। मैरिको ने कहा है, 'भारतीय व्यवसाय में, सभी श्रेणियों में सुधार के शुरुआती संकेत मार्च के शुरू तक दिख रहे थे, लेकिन पिछले 12 दिनों में चुनौती है।' जीसीपीएल ने कहा है कि भारत में उसके उत्पादों की मांग कोरोनावायरस से पहले तक मजबूत बनी हुई थी।

कंपनी ने कहा है, 'हालांकि मार्च के आखिरी 12 दिनों में बैक-एंड और फ्रंट-एंड आपूर्ति दोनों पर दबाव की वजह से मांग घट गई। हम सामान्य व्यापार के स्टॉक स्तर से संबंधित आंकड़े का इंतजार कर रहे हैं।' जीसीपीएल का यह भी कहना है कि आपूर्ति शृंखला के पुन: चालू होने से उसने अल्पावधि में धीरे धीरे हालात में सुधार दर्ज किया है और ज्यादा खपत घरेलू कीटनाशकों के लिए है।

मैरिको ने कम बिक्री के प्रभाव को दूर करने के लिए आक्रामक तौर पर लागत प्रबंधन की कोशिश शुरू कर दी है। मैरिको ने कहा है, 'सरकारी अधिकारियों के निर्देश के अनुरूप, जरूरी खाद्य एवं किराना उत्पाद बनाने वाली इकाइयों में उत्पादन काफी कम मात्रा में बरकरार है और उत्पादन में उच्च सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है।'

चौथाई क्षमता पर ब्रिटानिया संयंत्र का परिचालन

बीएस संवाददाता
बेंगलूरु, 9 अप्रैल

कोविड-19 लॉकडाउन के बीच, ब्रिटानिया के संयंत्रों में सिर्फ 25-30 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ परिचालन हो रहा है। ब्रिटानिया के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने एक निजी चैनल को बुधवार को बताया कि हालांकि अगले 5-6 दिन में उत्पादन में सुधार आने की संभावना है और कंपनी 70-75 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकती है। बेरी ने कहा, 'हमें कच्चे माल को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे संयंत्र फिलहाल 25-50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर रहे हैं, क्योंकि हम श्रमिकों को काम पर लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हमारी प्रमुख प्राथमिकता है, लेकिन इसे लेकर श्रमिकों में कुछ हद तक आशंका बनी हुई है।' उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मांग में तेजी निरंतर नहीं है। कंपनी 11 दिन तक के इन्वेंट्री स्तर को बरकरार रख रही थी जिसमें पिछले एक सप्ताह से कमी देखी जा रही है।

डिलिवरी के लिए अदाणी विल्मर ने किया स्विगी संग गठजोड़

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 9 अप्रैल

कोरोनावायरस के प्रसार पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच एफएमसीजी दिग्गज अदाणी विल्मर ने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर स्विगी संग करार किया है ताकि ग्राहकों के पास आवश्यक खाद्य सामग्री की डिलिवरी आसानी से हो सके। कंपनी खाद्य तेल और फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य उत्पाद बनाती है।

अदाणी विल्मर के डिप्टी सीईओ ए मलिक ने कहा, लॉकडाउन के कारण लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति शृंखला में अवरोध के चलते कंपनी ने स्विगी संग गठजोड़ किया है ताकि उनके ग्राहक अपने घर से बाहर निकले बिना कंपनी का सारा उत्पाद हासिल कर सके।

स्विगी के जरिये फॉर्च्यून की पूरी रेंज की डिलिवरी लखनऊ व कानपुर में अगले हफ्ते शुरू होने की संभावना है। अदाणी विल्मर का इरादा इसका विस्तार 13 और शहरों में करने का है, जिनमें दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलूरु शामिल है।

मलिक ने कहा, हमें भरोसा है कि स्विगी के जरिए सुविधाजनक डिलिवरी और अच्छी गुणवत्ता के हमारे उत्पाद सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को पूरी सेवा बेहतर तरीके से हासिल हो गई।

इस गठजोड़ के तहत अदाणी विल्मर स्पेशल कॉम्बो पैक लेकर भी आ रही है, जिसमें 4-5 उत्पाद होंगे और इसकी डिलिवरी स्विगी के जरिए होगी। कॉम्बो पैक क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएंगे और ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के मुताबिक इसका विस्तार किया जाएगा।

अपोलो टायर्स ने जुटाई रकम: अपोलो टायर्स ने निजी नियोजन के जरिये गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) आवंटित कर 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने बताया कि मौजूदा निर्गम 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य वाले 5,000 एनसीडी जारी करने के लिए है। *भाषा*

कोविड-19 के कारण अनिश्चितता

कॉग्निजेंट ने वापस लिया अनुमान

गिरीश बाबू
चेन्नई, 9 अप्रैल

कोरोनावायरस महामारी के संकट के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बीच कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस कॉरपोरेशन ने साल 2020 के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान वापस ले लिया है। कोविड-19 से खास तौर से ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी उद्योगों की क्लाइंटों की मांग प्रभावित हुई है। पहली तिमाही का राजस्व 4.22-4.23 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 2.7-2.9 फीसदी (स्थायी मुद्रा में 3.4-3.6 फीसदी) ज्यादा है।

कंपनी ने आज कहा कि इस तिमाही के पहले दो महीने में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन पटरी पर था और पिछले अनुमान को पीछे छोड़ रहा था। इसमें उत्तर अमेरिकी बाजार के मजबूत प्रदर्शन का अहम योगदान था। हालांकि मार्च के दूसरे हिस्से में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण कारोबार प्रभावित हुआ क्योंकि खास तौर से भारत व फिलिपींस में परियोजनाओं की डिलिवरी नहीं हो पाई क्योंकि कर्मचारी घर से काम करने लगे। इसके अलावा क्लाइंटों की मांग भी घटी, खास तौर से ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी उद्योग में।

कंपनी को आशंका है कि दूसरी तिमाही के दौरान इस महामारी के कारण क्लाइंटों की मांग और घटेगी क्योंकि कोविड-19 का समाज व अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा और यह विभिन्न उद्योगों में व्यापक अवरोध पैदा करेगा।

कंपनी ने कहा, हमारे कारोबार का लंबी अवधि का फंडामेंटल मजबूत है। हालांकि अप्रत्याशित संकट से पैदा हुई अनिश्चितता और प्रदर्शन का अनुमान सामने रखने की हमारी क्षमता पर इसके असर को देखते हुए कंपनी साल 2020 का प्रदर्शन अनुमान वापस ले रही है, जो 5 फरवरी 2020 को सामने रखा गया था। 5 फरवरी को कंपनी ने कहा था कि साल 2020 में सालाना आधार पर राजस्व की बढ़त की रफ्तार (स्थायी मुद्रा के लिहाज से) 2 से 4 फीसदी रहेगी, जिसमें कुछ निश्चित कंटेंट सर्विस बिजनेस से बाहर निकलने के कारण 100 आधार अंक का नकारात्मक असर शामिल है, जिसकी घोषणा पहले की गई थी।

कंपनी ने पहली तिमाही में सालाना आधार पर राजस्व में 2.8-3.8 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था, जिसमें कंटेंट सेवा कारोबार से बाहर निकलने के कारण 60 आधार अंक का अनुमानित नकारात्मक असर शामिल है।

पहली तिमाही के अनुमान 4.22-4.23 अरब डॉलर पर टिप्पणी करते हुए मुख्य कार्याधिकारी ब्रायन हम्फ्रीज ने कहा, तिमाही के पहले दो महीने में अपने कारोबार की रफ्तार को लेकर हम खुश हैं और मार्च में अपने सहयोगियों के समर्पण और पेशेवर अंदाज के आभारी हैं। इन दोनों चीजों ने हमें पहले घोषित राजस्व अनुमान हासिल करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कहा, अनिश्चितता के इस माहौल में हम एक दर्जन से ज्यादा उद्योगों के क्लाइंटों के साथ गहरे संबंध और मजबूत बैलेंस शीट के साथ हम बेहतर स्थिति में हैं, जो हमें ठोस वित्तीय लचीलापन मुहैया कराता है। कंपनी के 2.92 लाख सहायकों ने कारोबार पर कोविड-19 के सीमित असर के लिए तेजी से कदम बढ़ाया और इसके लिए उन्होंने अपनी डिलिवरी टीम के लिए घर से काम करने की व्यवस्था कर दी।

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के मैकलॉगिन ने कहा, हमें भरोसा है कि मजबूत बैलेंस शीट और मजबूत परिचानल व नकदी सृजन वाले कारोबार से हम इस अवरोध को पार करने में सक्षम होंगे।

भारत व फिलिपींस में एसोसिएट व उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों को अप्रैल में मूल वेतन का 25 फीसदी अतिरिक्त देने का ऐलान कंपनी पहले ही कर चुकी है।

महामारी पड़ी भारी

- कोविड-19 से खास तौर से ट्रैवल व हॉस्पिटैलिटी उद्योगों की क्लाइंटों की मांग प्रभावित हुई है
- पहली तिमाही का राजस्व 4.22-4.23 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है
- 5 फरवरी को कंपनी ने अनुमान जाहिर करते हुए कहा था कि साल 2020 में सालाना आधार पर राजस्व की बढ़त की रफ्तार (स्थायी मुद्रा के लिहाज से) 2 से 4 फीसदी रहेगी

धीमी रहेगी कर्ज देने की रफ्तार

दरों का बेहतर क्रियान्वयन मुख्य प्राथमिकता रहेगी

सुब्रत पांडा
मुंबई, 9 अप्रैल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा जोखिम है और फिलहाल कर्ज देने की वृद्धि दर कम रहने की संभावना है, जो कमजोर मांग तथा जोखिम को दर्शाती है।

आरबीआई ने कहा, 'क्रेडिट बाजार में मौद्रिक नीति को बेहतर तरीके से प्रसारित करना केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता होगी।'

वित्त वर्ष 2020 में गैर-खाद्य क्षेत्र में कर्ज देने की दर के साथ अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि 6.1 प्रतिशत पर रही जो पिछले साल की समान अवधि में 14.4 प्रतिशत थी।

आरबीआई के अनुसार, ऋण वृद्धि की सुस्ती सभी बैंक समूहों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों में दिखी थी। हालांकि, हालिया अवधि (दिसंबर 2019-मार्च 2020) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्रेडिट ऑफटेक में थोड़ी तेजी देखी गई है।

आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा 15 मार्च 2019 से 13 मार्च 2020 के दौरान कर्ज वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार रहा, निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 62.6 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 36.6 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के मामले में 0.8 फीसदी रहा।

साथ ही, मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बॉन्ड, डिबेंचर और सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों के शेयरों में निवेश, जो गैर-एसएलआर निवेश का एक बड़ा हिस्सा है, जो एक साल पहले के मुकाबले दूसरी छमाही में काफी नीचे रहा।

आरबीआई ने कहा, 'ऋण वितरण में कोई तेजी नहीं दिख रही और गैर-एसएलआर निवेश घट रहे हैं, ऐसे में बैंकों ने अपने एसएलआर पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। 28 फरवरी 2020 को बैंको की एनडीटीएल के अनुपात में एसएलआर 8.4 प्रतिशत के करीब थी, जबकि मार्च 2019 के अंत में यह 6.3 प्रतिशत थी।'

इक्रा रेटिंग्स में उपाध्यक्ष (फाइनैंशियल सेक्टर) अनिल गुप्ता कहते हैं, 'वित्त वर्ष 2021 में ऋण वृद्धि 6 प्रतिशत के दायरे में होगी। इस दौरान वृद्धिशील ऋण वृद्धि लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के करीब होगी। विस्तार को टालने के चलते कारोबारियों से कर्ज मांग न के बराबर होगी। तरलता की समस्या को दूर करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की मांग है। खुदरा क्षेत्र भी उधार लेने से परहेज करेगा और वहां नौकरी जाने तथा वेतन कटौती की संभावनाएं भी हैं।'

इस बीच, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 70-140 आधार अंकों कमी कर दी है। आरबीआई ने कहा, 'इससे मौद्रिक प्रसार के मोर्चे पर आगे बढ़ा जा सकता है।'

- वित्त वर्ष 2020 में गैर-खाद्य क्षेत्र में कर्ज देने की दर के साथ अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि 6.1 प्रतिशत पर रही जो पिछले साल की समान अवधि में 14.4 प्रतिशत थी
- आरबीआई के अनुसार, ऋण वृद्धि की सुस्ती सभी बैंक समूहों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों में दिखी थी
- वित्त वर्ष 2021 में ऋण वृद्धि 6 प्रतिशत के दायरे में होगी

नहीं लगा पाए जीडीपी का सही अनुमान

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वह भारत में आर्थिक मंदी किस तरह की होगी, इसका अनुमान लगाने में नाकाम रहा, यहां तक कि कोविड-19 की महामारी से पहले भी, जिसकी वजह उम्मीद से कम पूंजी निर्माण और कमजोर गतिविधियों का जारी रहना है, खास तौर से ग्रामीण इलाके में।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 27 तिमाही के निचले स्तर 4.7 फीसदी पर आ गई। दूसरी तिमाही में इसकी रफ्तार संशोधित कर 4.5 फीसदी से 5.1 फीसदी की गई थी। अक्टूबर 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में आरबीआई ने अनुमान जताया था कि दूसरी तिमाही की रफ्तार 5.3 फीसदी रहेगी जबकि तीसरी तिमाही में 6.6 फीसदी।

आरबीआई ने कहा, एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के लिहाज से वास्तविक नतीजा इन अनुमानों को दूसरी व तीसरी तिमाही में क्रमश: 20 आधार अंक व 190 आधार अंकों से कम करता है। दूसरी तिमाही में गिरावट का रुख उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, जिसे सकल पूंजी निर्माण और निजी उपभोग खर्च में कमजोरी ने नीचे धकेला। तीसरी तिमाही में अनुमान की गलतियां मुख्य रूप से सकल पूंजी निर्माण में तेज गिरावट के कारण हुई, जो जीडीपी की नई सीरीज में सबसे गहरा था।

अस्थमा दवा निर्यातकों को अमेरिका में सहूलियत

सोहिनी दास और उज्ज्वल जौहरी
मुंबई/नई दिल्ली, 9 अप्रैल

सिप्ला को उम्मीद से पहले मिली दवा के लिए मंजूरी, ल्यूपिन भी दौड़ में

अमेरिकी बाजार को निर्यात करने वाली भारतीय औषधि कंपनियों को कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप के बीच काफी सहुलियत मिल सकती है क्योंकि इस संकट के कारण औषधि नियामकों से मंजूरी तेजी से मिलने लगी है। श्वसन रोग के उपचार वाली दवाओं के बाजार की अग्रणी कंपनी सिप्ला ने आज कहा कि अमेरिकी औषधि नियामक यूएसएफडीए से उसे अस्थमा की दवा अल्बुटेरोल (इनहेलर) के लिए मंजूरी मिल गई है।

ल्यूपिन को इस दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी उम्मीद से पहले मिली है और इसका असर शेयर बाजार में भी दिखा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर सिप्ला का शेयर आज 52 सप्ताह की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पिछले बंद भाव के मुकाबले 13 फीसदी की बढ़त के साथ 579.5 रुपये पर बंद हुआ।

ल्यूपिन भी अमेरिका में अल्बुटेरोल के लिए आवेदन किया है और विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि यूएसएफडीए अब मंजूरी को प्राथमिकता दे सकता है। ल्यूपिन के शेयर में भी आज 11.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। एक विश्लेषक ने कहा, 'अल्बुटेरोल के लिए ल्यूपिन ने जिन संयंत्रों के लिए आवेदन किया है वे सुरक्षित हैं यानी वे यूएसएफडीए की जांच के दायरे में नहीं हैं। इसलिए उसकी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं।'

अमेरिका में अल्बुटेरोल इनहेलर एयरोसोल का बाजार करीब 2.8 अरब डॉलर का है। आईक्यूवीआईए के आकलन के अनुसार, मर्क शार्प और डोमे कॉर्प की दवा प्रोवेंटिल एवं उसकी प्राधिकृत जेनेरिक दवाओं की अमेरिका में पिछले 12 महीनों के दौरान बिक्री करीब 15.3 करोड़ डॉलर की रही। यूएसएफडीए से मिली इस मंजूरी से अमेरिकी बाजार में सिप्ला के लिए संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर होंगी। जबकि हाल में उसे कमजोर वृद्धि का सामना करना पड़ा था।

विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें यह मंजूरी वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के आसपास मिलने की उम्मीद थी लेकिन वह पहले मिल गई। एडलवाइस के अंकित हटाल्कर ने कहा, 'हम वित्त वर्ष 2021 में केवल सीमित बिक्री के साथ वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में यह मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहे थे। हमारे अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में इसकी बिक्री 5 से 6 करोड़ डॉलर हो सकती है।'

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस दवा का महत्त्व बढ़ गया है क्योंकि लोगों को श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में अस्थमा रोगियों की संख्या 2.6 करोड़ से अधिक है और उनमें करीब 70 लाख बच्चे हैं।

सिप्ला ने अपने अमेरिकी श्वसनरोग दवा पोर्टफोलियो के लिए यह दूसरी सकारात्मक घोषणा की है। पिछले शुक्रवार को उसने जेनेरिक एडवायर के लिए तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की थी। इससे जल्द ही कंपनी के लिए एब्रिविएटेड न्यू ड्रग ऐप्लिकेशन (एएनडीए) फाइलिंग के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

सिप्ला के एमडी एवं वैश्विक सीईओ उमंग वोहरा ने कहा, 'अल्बुटेरोल यूएसएफडीए द्वारा मंजूर प्रोवेंटिल का पहला जेनेरिक मीटरयुक्त डोज इनहेलर है। बाजार में डिवाइस आधारित यह दवा लाने वाली सिप्ला पहली कंपनी है।'

हिंडाल्को को ईयू से मिली एलेरिस के अधिग्रहण की इजाजत

देव चटर्जी
मुंबई, 9 अप्रैल

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को का शेयर गुरुवार को 7 फीसदी चढ़ गया क्योंकि उसकी सहायक नोवेलिस को 2.6 अरब डॉलर में एलेरिस कॉर्प के अधिग्रहण की अंतिम मंजूरी यूरोपीय आयोग से हासिल हो गई। ईयू की तरफ से तय शर्तों के मुताबिक, एलेरिस को सबसे पहले अपना बेल्जियम प्लांट लिबर्टी हाउस को 33.7 करोड़ डॉलर में बेचना होगा। कंपनी यह प्लांट लिबर्टी हाउस को बेचने के लिए सहमत हो गई है।

हिंडाल्को का शेयर 107 रुपये पर बंद हुआ क्योंकि जुलाई 2018 में घोषित अधिग्रहण के लिए मंजूरी अंतत: मिल गई। एलेरिस के अधिग्रहण से नोवेलिस को ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और बिल्डिंग ऐंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम उत्पाद की पेशकश करने में मदद मिलेगी। नोवेलिस का राजस्व मार्च 2019 में समाप्त वर्ष में 12.3 अरब डॉलर रहा था जबकि एलेरिस का राजस्व साल 2018 में 3.4 अरब डॉलर रहा था।

इस साल मार्च में अमेरिकी न्याय विभाग ने ऐलान किया था कि वह एलेरिस के साथ नोवेलिस के प्रस्तावित विलय को चुनौती देने वाले एंटी-ट्रस्ट मुकदमे का निपटारा कर लेगा, जब नोवेलिस ने एलेरिस का उत्तर अमेरिका का पूरा एल्युमीनियम ऑटो बिडी शीट ऑपरेशन बेचने पर सहमत हुई थी, जो इस महत्वपूर्ण उद्योग में प्रतिस्पर्धा का संरक्षण करेगा।

नोवेलिस इंक के अध्यक्ष व सीईओ स्टीव फिशर ने कहा, नोवेलिस ने नियामकीय समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अधिग्रहण पूरा करने के लिए तैयार है। इससे नोवेलिस को दुनिया की अग्रणी एल्युमीनियम रोलिंग व रीसाइक्लिंग के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी और वह ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगी।

यूरोपीय आयोग की मंजूरी के बाद नोवेलिस को अब सभी नियामकीय मंजूरी मिल गई है और वह एलेरिस का अधिग्रहण जल्द से जल्द पूरा करने की ओर बढ़ेगी।

आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अधिग्रहण की घोषणा करते समय कहा था, यह अधिग्रहण दुनिया की अग्रणी वैल्यू ऐडेड उत्पाद कंपनी के तौरपर नोवेलिस की स्थिति मजबूत करेगा। नोवेलिस और हिंडाल्को की मौजूदगी एशिया में डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम वैल्यू चेन में होगी और यह उसे इस इलाके में भविष्य की बढ़त के लिए स्थापित कर देगा।

बेल्जियम प्लांट लिबर्टी हाउस को 33.7 करोड़ डॉलर में बेचेगी एलेरिस

कोविड का असर : और 8-10 फीसदी घटेगी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री

आर्थिक सुस्ती, ऐक्सल लोड के नियमों, जीएसटी व अन्य मसलों के कारण पहले से ही दबाव मे रहा वाणिज्यिक वाहन उद्योग अब कोरोनावायरस के पप्रसार के कारण एक और चुनौती का सामना कर रहा है। इन वजहों से वित्त वर्ष 2021 में बिक्री 8-10 फीसदी और घट सकती है और सीवी ओईएम के लाभ व क्रेडिट पर दबाव बना रह सकता है।

इक्रा ने कहा कि अल्पावधि के लिहाज से हमने वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र पर अपना नकारात्मक परिदृश्य बरकरार रखा है क्योंकि आर्थिक बढ़त की रफ्तार सुस्त है और इस क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता व वित्तीय माहौल बेहतर न होने से कोरोनावायरस के हालिया प्रसार उसकी चुनौतियों में और इजाफा करेगा। महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं, लिहाजा मांग पर अवरोध अल्पावधि में बना रह सकता है। साथ ही बेड़ा परिचालकों की कमजोर वित्तीय स्थिति और बीएस-6 उत्सर्जन नियमों की ओर बढ़ने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का भी इस पर असर देखने को मिलेगा। *बीएस*

संक्षेप में

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोली की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (सीईएल) के विनिवेश के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख एक महीने और बढ़ाकर 16 मई कर दी है। कोरोनावायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन (बंद) के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इससे पहले निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सीईएल में सरकार की शत प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की थीं। बोली लगाने की अंतिम तारीख 16 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 16 अप्रैल किया गया था। दीपम ने अब कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थितियों के मद्देनजर बोली लगाने की अंतिम तारीख एक महीने और बढ़ाकर 16 मई कर दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली सीईएल की स्थापना 1974 में हुई थी। *भाषा*

खरीफ बुआई के लिए अगले सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया। आगामी खरीफ सत्र में फसलों की बुआई के संबंध में कांफ्रेंस 16 अप्रैल को होगी। खरीफ फसलों की बुआई दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ जून-सितंबर के दौरान होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ राष्ट्रीय कांफ्रेंस 16 अप्रैल 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगी। *भाषा*

साइबर अपराधों से बचने के लिए दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को स्पाईवेयर और रैंसमवेयर के खिलाफ सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण हैंडसेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल और साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी सहित अन्य अपराधों का खतरा भी बढ़ा है। परामर्श में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को अपडेट रखना, ऐप अपने ही मोबाइल हैंडसेट निर्माता या आधिकारिक स्टोर डाउनलोड करना आदि शामिल है। *भाषा*

इस वित्त वर्ष में सरकार की बाजार से पहली उधारी

अनूप रॉय
मुंबई, 9 अप्रैल

वित्त वर्ष के लिए पहली उधारी में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चल रहे बाजार भाव की तुलना में ज्यादा कूपन का भुगतान किया है, क्योंकि ट्रेडर्स ने आने वाले दिनों में आपूर्ति ज्यादा होने के हिसाब से कदम उठाए हैं।

सरकार ने बाजारों से 19,000 करोड़ रुपये उधारी ली है। इस पूरी राशि को सब्सक्राइब कर लिया गया है। प्रभावी रूप से 10 साल के बेंचमार्क प्रतिभूति का कट आफ यील्ड 6.53 प्रतिशत आया है, जिसका इस्तेमाल 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए किया गया। प्रचलित यील्ड की तुलना में कट आफ 6 आधार अंक ज्यादा रहा और मंगलवार को राज्य सरकार की बॉन्ड नीलामी की तुलना में यह करीब 22 आधार अंक ज्यादा है। बहरहाल ब्लूमबर्ग के मुताबिक 10 साल के लिए कट आफ आम सहमति से बनी धारणा की तुलना में सिर्फ 2 आधार अंक ज्यादा है। 10 साल का बॉन्ड यील्ड 6.49 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो नीतिगत रीपो दर की तुलना में 200 आधार अंक ज्यादा है। बॉन्ड बाजार में इस तरह की स्थिति बहुत ही दुर्लभ है और अब उम्मीद है कि रिजर्व बैंक सीधे द्वितीयक बाजार बॉन्ड खरीद की घोषणा करेगा।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

सरकार ने 40 साल के परिवक्वता पत्र के माध्यम से भी 6,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं और दो साल के परिपक्वता पत्र के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बोली पर्याप्त संख्या में आई। 10 साल के बॉन्डों के लिए 290 बोलियां मिलीं।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के फिक्स्ड इनकम के प्रमुख बद्रीश कुलहल्ली ने कहा- 'कट-ऑफ उम्मीद के मुताबिक ही रहा। जब तक लॉकडाउन जारी रहता है, बाजार की दिलचस्पी भी सीमित होगी। लेकिन इस अवधि के दौरान अगर यील्ड ऊपर जाता है, बाजार की धारणा नकारात्मक हो जाएगी।'

फर्स्ट रैंड बैंक में ट्रेजरी के प्रमुख हरिहर कृष्णमूर्ति ने कहा, 'निश्चित रूप से बाजार कमजोर है और राज्य सकार की नीलामी में ज्यादा यील्ड अपेक्षित था। उधारी की मात्रा को लेकर बाजारों में चिंता बनी हुई है, खासकर अगर अर्थव्यवस्था को बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत होती है।'

लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे राजकोषीय कदमों पर बाजार नजर बनाए हुए है।

जन स्माल फाइनैंस बैंक के कोषागार के प्रमुख गोपाल त्रिपाठी ने कहा, 'बाजार में तनाव नजर आ रहा है। हालांकि कट ऑफ बाजार की उम्मीदों के आसपास ही है, लेकिन कोरोना के कारण सरकार की ओर से होने वाली राजकोषीय घोषणाओं पर बाजार निर्भर है।'

बाजार से धन जुटाने के लिए राज्य सरकारों ने जी-सेक से 150 से 200 आधार अंक ज्यादा या नीतिगत रीपो दर की तुलना में 450 आधार अंक ज्यादा पर उधारी ली है। केरल ने मंगलवार को 15 साल के बॉन्ड पर 8.96 प्रतिशत भुगतान किया है, जबकि इसी के बराबर परिपक्वता की सरकार की प्रतिभूति 6.92 प्रतिशत पर बंद हुई। सरकार को इस माहौल में पहली छमाही में 4.88 लाख करोड़ रुपये उधार लेने होंगे। बैंक नकदी का समर्थन चाहते हैं ऐसे में रिजर्व बैंक के लक्षित दीर्घावधि रीपो परिचालन (टीएलटीआरओ) को भारी प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय बैंक 3 साल के लिए धन 25,000 करोड़ रुपये की नीलामी कर रहा था। लेकिन इसके लिए 1,13,470 करोड़ रुपये की बोलियां हासिल हुईं। यह धन टीएलटीआरओ के माध्यम से लिया गया, जिसका इस्तेमाल खासकर कॉर्पोरेट पेपर खरीदने में होगा।

एक बैंक के कोषागार के प्रमुख ने कहा, 'इससे पता चलता है कि बैंक इन पेपर्स में अपने पैसे का निवेश करने को इच्छुक नहीं हैं और इसलिए वे रिजर्व बैंक पर जोखिम डाल रहे हैं।' शेयर बाजार से तालमेल बिठाते हुए रुपये में कुछ तेजी आई है। आंशिक रूप से परिवर्तनीय मुद्रा इस समय 76.28 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई, जो इसके पहले 76.34 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी।

महंगी पड़ी उधारी

- सरकार ने बाजारों से ली **19,000** करोड़ रुपये की उधारी
- **10** साल की प्रतिभूति पर ली गई उधारी पर कट ऑफ यील्ड **6.53** प्रतिशत, सामान्य से ज्यादा
- **40** साल के परिपक्वता वाली प्रतिभूति के माध्यम से सरकार ने **6,000** करोड़ रुपये जुटाए
- **10** साल के बॉन्डों के लिए सरकार को **290** बोलियां मिलीं

सड़क निर्माण शुरू करने के आएंगे दिशानिर्देश

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के मामले में केंद्र सरकार अब विस्तार परियोजनाओं के लिए आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्य का विकल्प चुन सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ स्थापित मानकों के आधार पर परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि हर बुनियादी ढांचा परियोजना को प्राथमिकता है, लेकिन सड़कों को चौड़ा करना व उन्हें विस्तार देने का काम पहले किया जा सकता है क्योंकि इन परियोजनाओं को शुरू करना आसान है और इन पर काम शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत नहीं है।

इक्रा के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट और ग्रुप हेड शुभम जैन ने कहा, 'मौजूदा सड़कों के निर्माण के अलावा केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के लिए तमाम कामों के आवंटन व निर्माण की जरूरत है।'

इस मामले से जुड़े सड़क मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 'काम शुरू करने में कर्मचारियों का स्वास्थ्य एक अहम मानदंड होगा। जिन इलाकों में कामगार सुरक्षित रहेंगे, उन इलाकों में काम शुरू किया जा सकता है और अन्य परियोजनाओं में भी यही तरीका अपनाया जाएगा।'

बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना और अन्य ठेकों में कोई अंतर किए जाने की संभावना नहीं है और जहां तक काम शुरू किए जाने का सवाल है, यह पूरी तरह से श्रमिकों की स्थिति पर निर्भर होगा।

- सरकार सड़कों का काम शुरू करने के मामले में आसानी से हासिल होने वाले लक्ष्य का चयन कर सकती है
- हालांकि कामगारों के सेहत की सुरक्षा प्राथमिकता पर होगी और उन्ही इलाकों में काम शुरू किया जाएगा जहां काम करना सुरक्षित हो

भारतमाला परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2017 में मंजूरी दी थी। इसका मकसद देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 20,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण है, जिस पर 7 लाख करोड़ रुपये निवेश का अनुमान है। पहले चरण में 3 से 5 साल लगेंगे जबकि इस पर 5.5 लाख करोड़ रुपये लागत आएगी।

इस परियोजना का वित्तपोषण विभिन्न स्रोतों से होगा, जिसमें 2.09 लाख करोड़ रुपये की बाजार उधारी, 1.06 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश और 2.19 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क कोष या टोल संग्रह से जुटाया जाना शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर आने वाले खर्च का वित्त पोषण केंद्रीय सड़क बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) से आएगा। यह काम एजेंसी के आधार पर राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम और एनएचएआई द्वारा कराया जाएगा।

तमाम कृषि जिंसों के भाव एमएसपी से नीचे

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 9 अप्रैल

कई कृषि जिंसों के दाम उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आ गए हैं। श्रम, परिवहन और मंडी से संबंधित समस्याओं की वजह से कीमतों पर यह दबाव पड़ा है।

प्रमुख उत्पादन केंद्रों के नजदीक की मंडियों में आपूर्ति दबाव पैदा हो गया है। 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद परिवहन सुविधा ठप हो गई है।

कर्नाटक की सिडान मंडी में काला चना 4,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है, जो उसके 5,700 रुपये के एमएसपी की तुलना में 26 प्रतिशत नीचे है। इटावा (उत्तर प्रदेश) और साजा (छत्तीसगढ़) में बाजरा और गेहूं अपने एमएसपी के मुकाबले 22 और 30 प्रतिशत कम भाव पर बिक रहे हैं।

लॉकडाउन की वजह से धान, तिलहन और अन्य कृषि तथा बागवानी उत्पादों समेत सभी जिंसों में पिछले दो सप्ताहों में भारी गिरावट आई है। खेतों से मंडी तक और फिर उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने से इन जिंसों के भाव में भारी कमी आई है।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'मौजूदा समय में किसान परिवहन सेवा उपलब्ध न होने और श्रमिक किल्लत की वजह से अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। इसलिए वे नजदीक की मंडियों में बेच रहे हैं जिससे उन्हें एमएसपी से कम भाव मिल रहा है।'

हालांकि सरकार ने परिवहन में कुछ नरमी दी है और ट्रकों की अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति दी है, लेकिन खेतों से मंडियों तक और उसके बाद उपभोक्ताओं तक जिंसों की ढुलाई प्रतिबंधित बनी हुई है। इससे कृषि जिंसों की उपभोक्ता कीमतें चढ़ रही हैं।

- श्रमिक किल्लत, लॉजिस्टिक गतिविधि और मंडी बंद होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है
- काला चना और गेहूं समेत कई अनाज बिक रहे हैं एमएसपी से नीचे

इस बीच, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल पक गई है और उसकी कटाई का इंतजार हो रहा है। इसी तरह, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्याज, मौसमी फलों (अंगूर, अनार और आम शामिल) की कटाई अभी नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में किसानों को हरी और पत्तेदार सब्जियों की कटाई में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

कृषि विश्लेषक विजय सरदाना ने कहा, 'पकी हुई फसलों की कटाई में ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रम किल्लत या कटाई के बाद ढुलाई की समस्या की वजह से गैर-कटी फसलें कृषि उपज की स्पष्ट तौर पर बरबादी है। लेकिन इस परिस्थिति को लेकर सरकार के प्रयासों और उपज से प्राप्त होने वाले भाव के आधार पर अब किसानों को यह निर्णय लेना होगा कि अगले सीजन में क्या समान फसल की बुआई की जाए या अन्य फसलों पर ध्यान देना उचित होगा।'

अप्रैल से जून तक की अवधि निर्यातकों के लिए अहम

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

उद्योग निकायों ने एक सुर में मौजूदा पूर्ण बंदी को बढ़ाने के खिलाफ चेताया है। उनका कहना है कि बिना किसी उचित राहत के निर्यात को भारी नुकसान होगा और विदेश की बाजार हिस्सेदारी समाप्त हो जाएगी।

सूत्रों ने जानकारी दी है कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित दूसरे माल का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर के निर्यातक निकायों ने पिछले दो दिनों में वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी चिंता से अवगत कराया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विनिर्माण इकाइयों को तुरंत शुरू किए जाने की जरूरत है ताकि व्यापार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अप्रैल-जून निर्यात सीजन का लाभ उठाया जा सके।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी कहा, 'ऐसे समय पर जब चीन अपने फैक्टरियों को फिर से शुरू कर रहा और अतिरिक्त इन्वेंट्री को निपटाने के लिए बेचैन है, तब भारतीय निर्यातों को अब तक रद्द या स्थगित नहीं किए गए ऑर्डरों को पूरा करने में सक्षम बनाने की जरूरत है।'

उद्योग निकाय ने विनिर्माण को चालू रखने के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पृथक्करण स्थल बनाने और उसे सुचारु रखने का समर्थन किया है।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के भारत प्रमुख रवि सहगल ने कहा, 'विभिन्न उद्योगों में यह वैश्विक कारोबार का सबसे अहम समय है। एक ओर जहां घरेलू बाजारों में कुछ सुरक्षा हो सकती है, वहीं वैश्विक बाजार दूसरे देशों के दबदबे के लिए खुला पड़ा है। भारत उस मोर्चे पर नुकसान नहीं उठा सकता है।'

वैश्विक मांग घटने से
निर्यात को संकट

भारत के कुल निर्यात सौदे में इंजीनियरिंग उत्पाद की हिस्सेदारी एक चौथाई है। ईईपीसी इंडिया ने रेखांकित किया है कि शीर्ष के जिन 25 बाजारों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यातों की हिस्सेदारी 75 फीसदी से अधिक है उनमें से अधिकांश बड़े गंतव्य कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण बंदी या कठोर प्रतिबंधों में हैं। इनमें शीर्ष के तीन गंतव्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और जर्मनी हैं।

सहगल ने कहा, 'मार्च महीने की खेप में बाधा आई है। विदेशी खरीदार को यह बात समझाई जा सकती है और उन्हें एक महीने के लिए रोका जा सकता है लेकिन उसके बाद नहीं। यदि भारत इस महीने विश्व के लिए उत्पादन नहीं करता है तो वह 2020 के पूरे वर्ष के लिए विदेशी खरीदारों की योजना से बाहर हो जाएगा।'

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'हम मार्च में भी सुस्ती की उम्मीद कर रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में अप्रैल में भी मांग में गिरावट रहेगी, जो कमी की बड़ी वजह है।' फियो के मुताबिक कुल निर्यात ऑर्डर में से 30 प्रतिशत से ज्यादा अटक गए हैं।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक यूरोप के देशों व अमेरिका को किए जाने वाले परिधान निर्यात को झटका लगेगा, जो 2020 के गर्मियों के सीजन के लिए होने वाला था। कुल मिलाकर उद्योग बड़े पैमाने पर नकदी के संकट से जूझ रहा है और उसके पास खरीदारों की ओर से पैसे आने के बहुत कम विकल्प बचे हैं।आयात की लागत घटाने के लिए कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन टैक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन टी राजकुमार ने सुझाव दिया है कि सभी कच्चे माल, डाई, केमिकल्स, इंटरमीडिएटरीज, स्पेयर, एक्सेसरीज को एंटी डंपिंग शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क से छूट मिलनी चाहिए।

प्रधानमंत्री को लिखे गए एक पत्र में अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि इस उद्योग में 1.29 करोड़ लोग काम करते हैं और अगर सरकार तत्काल लक्षित आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं करती है तो इन पर मुसीबत आनी तय है।

उन्होंने कहा, 'परिधान निर्यात मौसमी उद्योग है और उत्पाद खराब होने वाले उत्पादों की ही तरह से हैं क्योंकि ये टेलर मेड, विशेष डिजाइन, विशेष फैशन के होते हैं और ऑर्डर रद्द होने के बाद अगले साल इनका मूल्य मामूली या कुछ भी नहीं रह जाता है।'

उद्योग के अनुमान के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत अपैरल इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग क्षेत्र में हैं। इसमें श्रमिकों पर आने वाला खर्च सबसे ज्यादा- उत्पाद की लागत का 25 से 30 प्रतिशत तक होता है।

मार्च तिमाही में घटी कार्यालयों की मांग

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 9 अप्रैल

कैलेंडर वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्यालय की जगह की खपत में 30 प्रतिशत की कमी आई है। संपत्ति सलाहकार जेएलएल की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 86 लाख वर्गफुट कार्यालय की जगह इस तिमाही में ली गई है। जेएलएस के मुताबिक इस तरह की तेज गिरावट इसके पहले 2017 की पहली तिमाही में आई थी, जब नोटबंदी के बाद खपत में 60 प्रतिशत गिरी थी।

जेएलएल में शोध के प्रमुख और कार्यकारी निदेशक सामंतक दास ने कहा, पट्टे के कुछ सौदे बातचीत के अंतिम चरण में हैं, जिन्हें टाल दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की पहली तिमाही में 86 लाख वर्गफुट नई परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत कम हैं। तीन बड़े बाजारों बेंगलूरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कुल खपत करीब 75 प्रतिशत रही है। मुंबई और चेन्नई में शुद्ध खपत 2020 की पहली तिमाही में 2019 की पहली तिमाही की तुलना में दोगुने से ज्यादा रही, शुरुआती दो महीनों में आईटी व आईटीएस क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर पट्टे पर जगह ली है।

खाद्यान्न की ढुलाई में 148 प्रतिशत की तेजी आई

शाइन जैकब और
संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

चालू वित्त वर्ष के पहले सप्ताह में खाद्यान्न, आटा और दलहन की ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 148 प्रतिशत बढ़कर 12.4 लाख टन हो गई है। इसके विपरीत अन्य जिंसों की रेलवे से ढुलाई में देशबंदी के कारण भारी कमी आई है।

इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि ढुलाई में तेजी की बड़ी वजह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों को अनाज की आपूर्ति है, जिससे कहीं इसकी कमी न होने पाए।

एफसीआई ने 24 मार्च से 14 दिनों में 662 रैक के माध्यम से 19 लाख टन खाद्यान्न की ढुलाई कराई है। इस दौरान रेलवे के 64 प्रतिशत रैक चावल और गेहूं की ढुलाई में इस्तेमाल हुए हैं, जो पंजाब और हरियाणा से भरे गए हैं। खाद्यान्न आटा और दलहन के अलावा अन्य जिंसों की ढुलाई में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कमी आई है।

वित्त वर्ष 21 के पहले सप्ताह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में सीमेंट की ढुलाई 98 प्रतिशत, लोहा और स्टील की ढुलाई 64 प्रतिशत, पेट्रोलियम की 47 प्रतिशत, खनिज एवं अयस्क की ढुलाई 39 प्रतिशत और कोयले व कोक की ढुलाई 29 प्रतिशत कम हुई है।

एक अधिकारी के मुताबिक सिर्फ उत्तर रेलवे जोन में अनाज लोडिंग के लिए रैक की औसत जरूरत 15 से बढ़कर 40 रैक प्रतिदिन हो गई है। इसमें तेजी की एक बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्न की लदान और इसकी कमी वाले राज्यों में तेजी से भेजा जाना है क्योंकि सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हर लाभार्थी को मुफ्त में 15 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा।

24 मार्च से 6 अप्रैल के बीच एफसीआई ने करीब 1.4 लाख टन खाद्यान्न रोजाना भेजा है, जो देशबंदी के पहले की तुलना में करीब 80 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा 1.3 लाख टन चावल और इतनी ही मात्रा में गेहूं की ढुलाई इस अवधि के दौरान आटा पीसने वालों और पैकेटबंद आटा तैयार करने वालों को हुई है।

खाद्यान्न की लदान और उसे उतारने के लिए एफसीआई और रेलवे ने मिल-जुलकर योजना तैयार की है। पहले एफसीआई पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे आपूर्तिकर्ता राज्यों से खाद्यान्न ढुलाई का कार्यक्रम देता है। उसके बाद रेलवे परिचालन की व्यवहार्यता के मुताबिक इस योजना को मंजूरी देता है।

अगले चरण में एफसीआई विभिन्न राज्यों में माल पहुंचाने की सूची देता है। जिन केंद्रों पर अनाज के रैक पहुंचाए जाने हैं उसका फैसला संबंधित जोन के डिप्टी चीफ ऑपरेशन मैनेजर एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक मिलकर करते हैं।

अगर खाद्यान्न, आटा और दलहन उतारे जाने की बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में यह पिछले साल की समान अवधि के 7.8 लाख टन से 41 प्रतिशत बढ़कर 10.9 लाख टन हो गया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल और मिजोरम ने केंद्र के कोटे से गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्रा लेना शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वस्त किया है कि राशन की दुकानों में वितरण के लिए उसके गोदामों में गेहूं व चावल पर्याप्त मात्रा में है।

केंद्र के पूल में भारत के गेहूं और चावल का स्टॉक 10 मार्च 2020 को अनुमानित रूप से 777.2 लाख टन था, जिसमें 192.4 लाख टन धान शामिल है। अगर 3 साल का औसत देखें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के तहत खाद्य वितरण के लिए साल में 540 लाख टन अनाज की जरूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 2020-21 सीजन के लिए 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू किए जाने के पहले गोदामों में एक साल से ज्यादा अवधि तक वितरण के लिए अनाज मौजूद है।

गुरुवार को कोयंबटूर रेलवे स्टेशन पर खाने के पैकेट और दवाइयां ट्रेन में लादते कर्मचारी। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देशबंदी में इसे चेन्नई ले जाया जा रहा है *फोटो-पीटीआई*

- वित्त वर्ष 21 के पहले सप्ताह में खाद्यान्न, आटा दाल की ढुलाई 148 प्रतिशत बढ़ी
- अनाज लोडिंग के लिए रैक की औसत जरूरत 15 से बढ़कर 40 रैक प्रतिदिन हुई
- खाद्यान्न, आटा, दाल छोड़ दें तो और सभी जिंसों की ढुलाई में आई है कमी
- पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में पहुंचाया जा रहा है खाद्यान्न

बीएस सूडोकू 3711

परिणाम संख्या **3610**

			7	3	1		4	
								2
5		6		4				
		9				7		
			8			2	5	
	1			6			3	
		1			6			
	2	7	3					1
				2		4		

8	3	7	4	2	9	5	6	1
4	9	5	1	6	8	2	7	3
2	1	6	5	3	7	8	4	9
5	4	9	3	7	6	1	8	2
3	6	8	2	4	1	7	9	5
7	2	1	8	9	5	6	3	4
1	8	4	7	5	3	9	2	6
6	7	2	9	1	4	3	5	8
9	5	3	6	8	2	4	1	7

कैसे खेलें? आसान

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 43

समझदारी भरा निर्णय

सरकार ने देश के आपातकालीन रिजर्व में पेट्रोलियम भंडार को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। यह फैसला कई स्तरों पर समझदारी भरा और बेहतर है। कीमतें कम होने पर ज्यादा खरीदारी करना आर्थिक दृष्टि से अच्छा कदम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस महीने की शुरुआत के न्यूनतम स्तर से काफी सुधर गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1 अप्रैल को 25 डॉलर प्रति बैरल से कम थी और अब यह 10 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ चुकी है। इसके बावजूद यह पिछले वर्ष के औसत से 22 डॉलर प्रति बैरल सस्ता है। उस वक्त यह 57.70 डॉलर प्रति बैरल था।

आपातकालीन पेट्रोलियम भंडारण के क्षेत्र में भारत की क्षमता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस दौर में होनी चाहिए थी। फिलहाल यह 4 करोड़ बैरल से कम है। यह देश की 10 दिन से भी कम की मांग पूरी करने में सक्षम है। बहरहाल, फिलहाल मंगलूरु, विशाखापत्तनम और पडूर स्थित तेल भंडारण केंद्रों में केवल 1.5 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल भंडारित करने की क्षमता है। प्रश्न यह है कि यह अतिरिक्त तेल भंडार कहां से आएगा? सरकार ने मूलरूप से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों से समझौते करने के प्रयास किए ताकि वे अपना तेल भारत में भंडारित कर सकें। परंतु वह प्रयास फलीभूत नहीं हो सका। ऐसी खबरें हैं कि सरकार इन क्षेत्रों में भंडारण के लिए तेल खरीदेगी या उसकी जब्ती करेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात से 50 लाख बैरल से अधिक तेल खरीदने के प्रयास जारी हैं और पडूर के लिए 90 लाख बैरल तेल खरीदा जाना है। परंतु जानकारी यह भी है कि सरकार ने अपने तेलशोधक कारखानों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू मांग में आई करीब 50 फीसदी की कमी के कारण अपनी अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति को आपातकालीन पेट्रोलियम रिजर्व में भंडारित करें। इन रिफाइनरी को इसकी भरपाई कैसे की जाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।

फिलहाल भंडारण पर जोर है क्योंकि दुनिया भर में तेल उत्पादन इकाइयां लबालब हैं। इस हद तक कि सिटीग्रुप ने कहा है कि केवल एक तिमाही में ही दुनिया में एक अरब बैरल से अधिक तेल भंडारित हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भंडारण की कुल क्षमता 6 अरब बैरल की है लेकिन इस समय केवल 1.6 अरब बैरल की क्षमता ही रिक्त है।

भंडारण क्षमता की कमी ने अमेरिका में कुछ उत्पादकों को अपनी कीमतें शून्य से कम करने पर विवश किया है। यानी वे लोगों को अपना तेल ले जाने के लिए भुगतान कर रही हैं। दक्षिण कोरिया और चीन ने हाल के वर्षों में अपने यहां तेल भंडारण क्षमता पर काफी काम किया है। भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। करीब 5 करोड़ बैरल की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की योजना बनाई गई है लेकिन वैसा करने से भी हम केवल 20 दिन के आयात के बराबर तेल ही भंडारित कर पाएंगे। हमें कम से कम एक माह तक के उपयोग का तेल भंडारण करने की क्षमता विकसित करनी होगी।

भारत के लिए यह दर्शाने का भी उपयुक्त समय है कि वह अपना दायित्व समझने वाला पेट्रोलियम उपभोक्ता देश है और कच्चे तेल के बाजार को स्थिर बनाने में उसकी भूमिका है। उत्पादन में संभावित कटौती को लेकर अमेरिका, सऊदी अरब और रूस के बीच लगातार चल रहे विवादों के बीच जब भारत के पेट्रोलियम मंत्री शुक्रवार को जी20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो बड़े उत्पादकों के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता चाहता है लेकिन वह कीमतें भी उचित चाहता है। उत्पादन जारी रखने के प्रयास की मदद और भंडारण क्षमता की कमी को दूर करना इस दिशा में दो अहम कदम होंगे।

अजय मोहंती

आखिरी मौका ही रहे 'विवाद से विश्वास'

कर विवाद संबंधी मुकदमों के निपटारे के लिए हमें नवाचारी समाधानों की जरूरत है। विवाद से विश्वास योजना इस पहेली में एक खांचा भर है। बता रहे हैं **मुकेश बुटानी** एवं **तरुण जैन**

विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' विधेयक (योजना) को हाल ही में संसद में पारित कर दिया गया। कई लोगों ने इस विधेयक के पारित होने पर खेद जताते हुए कहा कि यह ईमानदार करदाताओं के साथ अन्यायपूर्ण मोलभाव करता है क्योंकि नैतिक मानदंडों से विकृत माने जाने वाले आचरण में लिप्त लोगों को यह रियायत देता है।

इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही इस कानून के साथ संवैधानिकता की परिकल्पना संलग्न हो गई है। अब करदाता लंबित कर मामलों के संदर्भ में लागत-मुफीद विश्लेषण करेंगे, मुकदमों को बंद करने के लिए विवरण जमा करेंगे और इन विवादों पर अदालती कार्यवाही जारी रखने की संभावना भी खत्म कर देंगे।

विवाद से विश्वास योजना को 2019 में अप्रत्यक्ष कर मामलों के लिए लाई गई ऐसी ही समाधान योजना की तार्किक परिणति के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली योजना के तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपये के कर विवादों का निपटारा किया गया था। मुकदमों को बंद करने के एक तात्कालिक उपाय के तौर पर यह तदर्थ कर विवाद समाधान योजना करदाताओं का नजरिया पेश करने की बात करती थी। इस संपर्क-सेतु को जोड़ने की जरूरत है और नई योजना से संबद्ध नैतिक सवालों से दूर रहने की भी जरूरत है। अप्रत्यक्ष करों के लिए लाई गई योजना में 30 फीसदी बकाया कर का भुगतान कर विवाद खत्म करने का प्रावधान था लेकिन विवाद से विश्वास योजना में समूची कर राशि के भुगतान (राजस्व विभाग की दाखिल अपील के मामले में यह 50 फीसदी भुगतान की बात करता है) की जरूरत है जो इस योजना को किसी तरह की 'माफी' योजना साबित करने के लिए नाकाफी है। चर्चा के लिए वाजिब कर कटौती के लिए नाकाम होने पर व्यय की अस्वीकृति से संबंधित मामले को ही लेते हैं। ऐसे मामलों में यह संभव है कि कमाई वाले करदाता ने समूची आय पर कर का भुगतान कर दिया है और इस तरह सरकार को राजस्व की कोई क्षति न हुई हो। इसके बावजूद, ऐसे मामलों में भी अस्वीकृति को लागू किया जाता है और चूककर्ता कटौतीकर्ता पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। जिन मामलों में कर कटौती करने वाले समूची कर राशि देने के लिए आगे आते हैं उनमें इसे किसी भी तरह से माफी योजना नहीं बताया जा सकता है।

इस निरर्थक कवायद में किसी को वह बड़ी तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए कि यह योजना एक पहेली का एक हिस्सा भर है। पिछले दशक में सरकार ने कर संबंधी मुकदमों की 'बुराई' पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक समग्र राष्ट्रीय मुकदमा नीति को आकार देना ऐसा ही एक कदम था जिसने मुकदमा दायर करने की सोच पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इसी तरह राजस्व अपीलों के लिए क्रमिक रूप से मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं। कई मामलों में प्रतिकूल फैसले आने पर भी राजस्व विभाग ने आगे और अपील न करने के संकल्प के मद्देनजर उन्हें स्वीकार कर लिया। मसलन, जनवरी 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले पर मुहर लगा दी थी जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के साथ जारी कीमत संबंधी विवादों को खत्म करने की बात कही गई थी। इस तरह के सुधारात्मक कदमों के बारे में पहले नहीं सुना गया था। इनके बावजूद कर-मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा भी है कि विवाद से विश्वास योजना 'उत्पीड़न' करने वाले मुकदमों को बंद करने का एक और तरीका है।

नवाचारी उपायों के साथ समाधान की भावना को बनाए रखने की सख्त जरूरत है। अगले कदम के तौर पर प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों, खासकर कर-विवादों में मध्यस्थता की पहल, को राजकोषीय कानूनों में जगह दी जानी चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद निपटान संस्थानों- मसलन, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण और विवाद समाधान पैनल में उत्साह का संचार करने के लिए शिद्दत से कोशिश करना आज के वक्त की जरूरत है। नीतियों का खाका तैयार करने वालों को लंबित विवादों की समीक्षा कर उन मामलों अलग करना होगा जिनमें सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी देखी जाती है। ऐसा करने पर कानूनी संशोधनों या प्रक्रियागत रियायतों के जरिये बुद्धिमान मुद्दा-आधारित समाधान निकलकर सामने आ पाएंगे।

हालांकि मनोदशा में बदलाव की जरूरत सबसे बड़ी है। सभी तरह के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की नियमित कवायद पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार को एक नई समीक्षा व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है जो निर्णय तक पहुंचने के लिए राजस्व विभाग के फील्ड-ऑफिसरों के अहम पर आधारित न हो और यह सुनिश्चित करे कि केवल कानून के बारे में ठोस सवालों से संबंधित विवादों को ही अदालत तक ले जाया जाए। शायद अपील दायर करने का फैसला लेने वाले अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक तौर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) फिल्टरिंग प्रणाली की तरह एक आंतरिक समीक्षा बोर्ड का गठन कर सकता है जो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली अपीलों के बारे में फैसला लेने के लिए जिम्मेदार होगा। बोर्ड के स्तर पर एक अकेली संस्था बढ़ते विवादों को सीमित करने के अलावा करदाताओं के बीच सामंजस्य रखने, अपील प्रस्तावों के बारे में रुझानों के बदलाव और एक समीक्षा मशीनरी के तौर पर काम करेगी। सामान्य वंचना-रोधी नियम (जीएएआर) के बारे में गठित अनुमति पैनल से इसकी साम्यता देखी जा सकती है लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ऐसे सशक्त पैनलों की मौजूदगी कर अधिकारियों को नियमित आदेश जारी करने के बजाय सजगता से काम करने के लिए बाध्य करती है।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह आश्वासन दिया था कि वह 1997 में लाई गई स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वीडीआईएस) को औचित्य के आधार पर निरस्त करने से हुए सार्वजनिक अपमान से बचने के लिए भविष्य में ऐसी कोई भी योजना नहीं लेकर आएगी। विवाद से विश्वास योजना को इस तरह की आखिरी योजना ही रखा जाए और कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए नवाचारी समाधान तलाशे जाएं। इस योजना से संबंधित सवालों के जवाब देने और इसके लाभों को 30 जून तक बढ़ाने में सीबीडीटी ने जिस तरह की तेजी दिखाई है उससे यह योजना करदाताओं के लिए शानदार मौका है।

(लेखक बीएमआर लीगल फर्म के साझेदार हैं)

केंद्र की वित्तीय स्थिति पर भारी इस वर्ष की छाया

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

नया वित्त वर्ष शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार को 2020-21 के दौरान राजस्व के मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना है। यह चुनौती न केवल कोविड-19 के प्रभाव से उपजेगी बल्कि वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व संग्रह का बढ़ाचढ़ाकर लगाया गया अनुमान भी इसकी वजह होगा।

सबसे पहले 2019-20 के राजस्व संग्रह प्रदर्शन को बजट के संदर्भ में देखते हैं। वर्ष 2019-20 में सकल कर राजस्व के 21.63 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान संशोधित अनुमानों में जताया गया था। परंतु अब यह स्पष्ट है कि वास्तविक सकल कर राजस्व 19.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। यानी इसमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आएगी। यह अनुमान उल्लिखित राजस्व संग्रह आंकड़ों और 2019-20 के पहले 11 महीनों के रुझान पर आधारित है। पूरे वर्ष का प्रत्यक्ष कर संग्रह केवल 10.27 लाख करोड़ रुपये रहने की आशा है जबकि संशोधित अनुमान में इसके 11.7 लाख करोड़ रुपये रहने की बात कही गई थी। यहां भी 1.43 लाख करोड़ रुपये की कमी है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी संग्रह के 4.95 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 5.14 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान से कम है यानी 19,000 करोड़ रुपये की कमी। जीएसीटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह भी अनुमान से 2,5000 करोड़ रुपये कम रहा।

सरकार के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2019-20 में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह के क्रमश: 1.05 लाख करोड़ रुपये और 1.97 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। कोविड-19 के चलते मार्च में पेट्रोलियम खपत और आयात में भारी कमी आई है। यदि मार्च में सीमा और उत्पाद शुल्क फरवरी की दर से बढ़ते तो भी पूरे वर्ष का संग्रह 1.15 लाख करोड़ और 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो पाता।

यदि विनिवेश प्राप्तियों में आने वाली करीब 50,000 करोड़ रुपये की कमी को इसमें शामिल किया जाए तो कुल राजकोषीय घाटा 2.18 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी के एक फीसदी से अधिक होगा। परंतु केंद्र के राजकोषीय घाटे पर इसका असर कुछ कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी व्यय में कुछ बचत हो सकती है। इससे घाटे का विस्तार रोका जा सकेगा। सरकार को कुछ व्यय की भरपाई बजट से इतर उधारी से करनी होगी। अहम बात यह है कि कर राजस्व में कमी का 70 फीसदी ही केंद्र सरकार वहन करेगी।

ध्यान रहे कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गत वर्ष सकल कर संग्रह का 30 फीसदी राज्यों को बांट दिया गया था। यदि वास्तविक संग्रह की तुलना में कमी आती है तो केंद्र को केवल 70 फीसदी यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बाकी बोझ राज्य उठाएंगे।

ऐसे में न केवल केंद्र बल्कि राज्यों पर भी राजस्व संग्रह कमी का सीधा असर होगा। हालात ज्यादा बिगड़े तो 2019-20 में केंद्र का राजस्व घाटा 0.7 फीसदी बढ़ सकता है और वास्तविक घाटा जीडीपी के 4.5 फीसदी के बराबर हो सकता है। जबकि संशोधित अनुमान 3.8 फीसदी था।

वर्ष 2019-20 में अधिकांश राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को गहरा झटका लगेगा। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी तक हो सकता है। अब यह तय है कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिन 19 राज्यों ने घाटे को 3 फीसदी के भीतर रखने की बात कही थी, उनमें से कई का घाटा बढ़ेगा।

परंतु चिंता केवल इतनी नहीं है। बड़ी चिंता यह है कि 2019-20 में कर राजस्व संग्रह में कमी का असर 2020-21 पर नजर आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि 12 फीसदी की नॉमिनल राजस्व संग्रह वृद्धि दर कोविड-19 के प्रसार के बाद दूर की कौड़ी है। 2019-20 में 19.62 लाख करोड़ रुपये के कमतर कर राजस्व संग्रह के साथ 2020-21 में 24.23 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें 23 फीसदी से अधिक की वृद्धि हासिल करनी होगी। यानी बजट में उल्लिखित दर के लगभग दोगुना। मौजूदा दौर में कोविड-19 के प्रभाव के बीच यह नामुमकिन लगता है।

यदि मान लिया जाए कि 2020-21 की नॉमिनल वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और कर उछाल (टैक्स बॉयन्सी) 1.2 फीसदी बनी रहेगी तो दोनों मानकों पर यह हकीकत से दूर नजर आता है। परंतु इन अनुमानों के आधार पर भी अनुमानित कर उछाल दर 1.6 तक ही जा पाएगी। यह दर भी आर्थिक मंदी के बीच लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। दूसरी ओर, विनिवेश प्राप्तियों में 223 फीसदी का इजाफा करना असंभव है और इससे सरकार का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और भी अप्राप्य हो जाएगा।

ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राजस्व संग्रह में संभावित गिरावट से अनभिज्ञ है। यह सही है कि उसने चालू वर्ष के अपने उधारी कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया है लेकिन कम राजस्व संग्रह की स्थिति में सरकारी वित्त पर से दबाव कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने वेज ऐंड मींस एडवांसेस (डब्ल्यूएमए)की सीमा को चालू वर्ष की पहली छमाही में केंद्र के लिए 60 फीसदी और राज्यों के लिए 30 फीसदी बढ़ा दिया है।

डब्ल्यूएमए वह तरीका है जिसकी मदद से केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व और व्यय की अस्थायी विसंगति से उबारा जाता है। परंतु आरबीआई पहले ही कह चुका है कि यदि केंद्र अपनी डब्ल्यूएमए सीमा का 75 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर लेता है तो वह बॉन्ड जारी करने पर विचार करेगा। केंद्र जरूरत पड़ने पर अपनी उधारी कभी भी बढ़ा सकता है।

हो सकता है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाए कि चालू वर्ष में केंद्र के कर राजस्व अनुमान गलत कैसे हो गए। परंतु कोविड-19 की लंबी छाया को 2019-20 की राजस्व कमी ने और गहरा बना दिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

कानाफूसी

घर पर एफआईआर

मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और इस बीच प्रशासन भी इसे लेकर कड़ा रुख अपना रहा है। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने तय किया है कि अनिवार्य वस्तुओं की तरह प्रदेश में एफआईआर की भी होम डिलिवरी की जाएगी यानी उसे लोगों के घर पहुंचाया जाएगा। 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसे आरोपितों के घर पहुंचाया जाएगा। पुलिस ये एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन डिटेक्शन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने ऐस्मा कानून लागू कर दिया है और इंदौर-भोपाल समेत कई जिलों में लॉकडाउन को और कड़ा कर दिया है जिससे कोरोनावायरस के प्रसार को कम किया जा सके।

दवा के बदले टीका?

भारत द्वारा कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली पैरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर से प्रतिबंध शिथिल करने से अमेरिका हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 2.9 करोड़ खुराक खरीदने में सक्षम हो गया। इसके एक दिन बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या इसके बदले में भारत को कुछ मिलेगा? थरूर ने कहा कि चूंकि भारत ने स्वयं यह प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है इसलिए अमेरिका को कोविड-19 का कोई भी टीका बनने पर भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत सरकार ने इस महामारी के दौरान मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए यह एकबारगी रियायत प्रदान की है। भारत को श्रीलंका और नेपाल से भी ऐसा अनुरोध हासिल हुआ है और वह इनका अध्ययन कर रहा है।

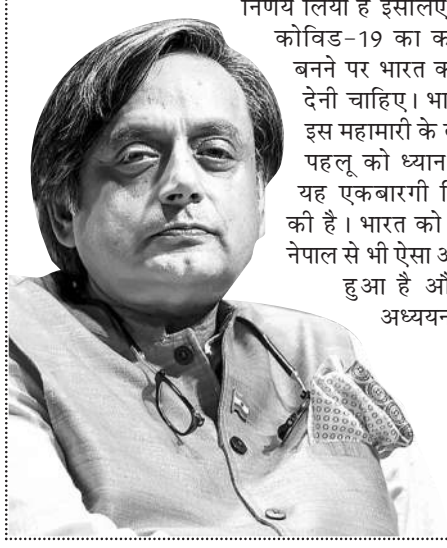

आपका पक्ष

कोरोना से जंग में भारत तैयार

लॉकडाउन में हम कितने सफल रहे हैं यह आने वाले समय में दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि कोरोना के प्रसार की रफ्तार धीमी होगी तथा हमारे सामने उस प्रकार का खतरा नहीं होगा, जैसा कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद नतीजे जो भी रहें लेकिन एक नतीजा साफ दिख रहा है कि हम इस खतरे को फिलहाल रोकने में सफल होते दिख रहे हैं। जिस तेजी से दुनिया के अन्य देशों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, वैसा भारत में नहीं है। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र, राज्य सरकारों की हर एजेंसी जुट गई है। देश में सरकारी प्रयोगशालाएं निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है, जिनके देशभर में 20,000 से ज्यादा केंद्र हैं। इतना ही नहीं, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा उपचार एवं राहत कार्य में लगे अन्य

लोगों के लिए निजी बचाव उपकरण (पीपीई) की भारी कमी थी, लेकिन पिछले दिनों में इस दिशा में शानदार कार्य किया गया है। डीआरडीओ ने ऐसे उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर से लेकर हर किस्म के पीपीई अब देश में बनने लगे हैं। रेलवे ने अपनी ट्रेनों, कोचों को क्वारंटीन केंद्रों और आइसोलेशन वार्ड में बदलने का

लॉकडाउन के बाद भी संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर ज्यादा कड़ाई बरती जा रही है

फैसला किया है। अर्द्धसैनिक बलों और सेना ने पहले से क्वारंटीन व उपचार की सुविधाएं विकसित की हैं। जरूरत पड़ी तो सेना जरूरतमंद इलाकों में चंद घंटों में क्वारंटीन और आइसोलेशन सुविधाएं विकसित कर सकती है। इसी प्रकार देश के दवा वैज्ञानिकों ने भी कमर कस ली है। मौजूदा दवा के परीक्षण के साथ नई दवा की खोज शुरू हो गई है। अगर दुनिया में कहीं भी कोरोना की दवा या टीका बनाया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसका उत्पादन देश में भी करना संभव हो जाएगा, क्योंकि यह क्षमता देश में है। ऐसी नई दवाओं पर पेटेंट कानून लागू नहीं होता है। लॉकडाउन के कारण लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। इसीलिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देकर लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश भी की गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान हुई तैयारी हमारे काम आएगी और इस महामारी से निपटने में हमें जीत मिलेगी।

सुजीत कुमार, बिलासपुर

अदालत के सुझाव पर अमल हो

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई अस्पतालों में में कोविड-19 वायरस की जांच हो रही है। कुछ निजी अस्पताल भी यह टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां इसका शुल्क बहुत अधिक है जो निम्नवर्गीय और मध्यवर्गीय परिवार के लिए बहुत अधिक है। यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम टेस्ट हुए हैं। जितने अधिक टेस्ट होंगे उतने अधिक संक्रमित लोगों का पता चल सकेगा और उनका इलाज संभव हो सकेगा। सरकारी अस्पताल अभी भी प्रतिदिन अधिक संख्या में कोविड परीक्षण करने में सक्षम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि निजी अस्पतालों में भी इस टेस्ट को कम शुल्क या मुफ्त कराने की व्यवस्था करे। इस निर्देश पर जल्दी अमल किया जाना चाहिए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 10 अप्रैल 2020 शुक्रवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

मजदूर लाओ, उत्पादन शुरू कराओ

दिल्ली सरकार ने श्रमिक संगठनों से की अपील, ममता ने कामगारों वाली टैक्सियों को इजाजत दी

अर्चिस मोहन

राष्ट्रीय राजधानी के कारखानों और गोदामों में काम करने और जरूरी वस्तुओं के परिवहन और वितरण के लिए कामगारों का इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक संगठनों से सहयोग करने का कहा है।

देश भर में लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाए जाने की आशंका है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें कुछ औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए जूझ रही हैं क्योंकि देश के शहरों, कस्बों और गांवों में जरूरी वस्तुओं के स्टॉक फिर से तैयार करने की जरूरत है। राज्य सरकारों का कहना है कि शहर के कारखानों और गोदामों में काम करने के लिए पर्याप्त कामगार नहीं हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद विशेष रूप से दिल्ली जैसे शहरों से भारी तादाद में दूसरे राज्यों के कामगार चले गए।

बुधवार को दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त ने सभी पंजीकृत श्रमिक संगठनों से कारखानों और गोदामों की मदद करने में मदद करने, समन्वय करने और काम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में

लॉकडाउन की वजह से दिल्ली जैसे शहरों से मजदूर कर गए हैं पलायन *फाइल फोटो*

कामगारों का इंतजाम करने की अपील जारी की। अपील में दिल्ली सरकार के सचिव सह श्रम आयुक्त मनोज कुमार ने कहा, 'यह वक्त की मांग है ताकि दिल्ली के नागरिकों को जरूरी खाद्य सामग्री और किराने की आपूर्ति की जा सके।'

गुरुवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से कहा कि उनकी सरकार ने कामगारों को एक-जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ टैक्सियों की आवाजाही की अनुमति दी है। ट्रकों पर तीन अतिरिक्त लोगों को जाने की इजाजत दी गई है जो आवश्यक वस्तुओं की लाने-भेजने के दौरान माल चढ़ाने और उतारने में मदद कर सकते हैं। माल ढोने वाले छोटे-मझोले वाहनों को भी आवश्यक वस्तुओं के लिए गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य में चाय बागानों को भी 15 प्रतिशत कामगारों की सीमित संख्या के साथ खुला रखने की अनुमति दी गई है ।

उन्होंने कहा कि उन उद्योगों को अपवाद के तौर पर अनुमति दी जा रही है जहां लगातार काम जरूरी है। संयंत्र खोलने से जुड़ी याचिकाओं पर हर मामले के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने स्पष्ट किया कि केवल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी।

गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ फैक्ट्रियां खासतौर पर आटा और दाल मिलें अपना परिचालन शुरू करें। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में आटा मिलें बंद हो गई थीं और कई सामानों और सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे।

कोरोना के लिए आपात कोष

रुचिका चित्रवंशी

सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने और भविष्य में बीमारी के प्रकोपों से बचाव की तैयारी के लिए 15,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कोष में 7,774 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तात्कालिक जरूरत पूरी करने में किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग एक से चार साल तक की मध्यम अवधि में किया जाएगा।

इस धनराशि में से ज्यादातर का उपयोग देश में आपात हालत से निपटने की तैयारी, महामारी पर अनुसंधान को मजबूत करने, बहु-क्षेत्र राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया, 'यह कोष विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन कदम के रूप में बनाया गया है। हमने इस कोष के बारे में राज्यों को जानकारी दी है और व्यापक दिशानिर्देशों के साथ और सूचनाएं साझा की जाएंगी।' इस कोष का इस्तेमाल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क और वेंटिलेटर की खरीद में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सामुदायिक निगरानी, अस्पतालों के अपग्रेड करने और एंबुलेंस में भी किया जा सकता है।

इस योजना का पहला चरण जून 2020 तक लागू किया जाना है। पहले चरण में जो काम किए जाने हैं, उनमें कोरोनावायरस के लिए विशेष अस्पताल खोलना, आइसोलेशन ब्लॉक, अतिरिक्त मानव संसाधन, ऑक्सिजन आपूर्ति, अस्पतालों को संक्रमण मुक्त बनाने, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। इस समय कोविड-19 की जांच 223 लैब में हो रही है, जिनमें 157 सरकारी और 66 निजी लैब शामिल हैं। मंत्री समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, जिसमें संक्रमण को रोकने की रणनीति, प्रबंधन प्रयासों और पीपीई और एन95 मास्क की उपलब्धता पर चर्चा की गई।

प्रवासी श्रमिकों के ब्योरे से उन्हें काम पर लाने में मिलेगी मदद

पृष्ठ 1 का शेष

रोजगार की इस सूची में कृषि, घरेलू काम, रिक्शा चलाना, सुरक्षा सेवा, ईंट भट्ठा में काम, वाहन की मरम्मत का काम, खाद्य प्रसंस्करण, इमारत और निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। नियोक्ताओं से क्षेत्रवार डेटा मांगे जाएंगे। राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न जिना प्रशासन से ये जानकारियां एकत्र की जाएंगी। प्रवासी मजदूरों का विवरण जुटाने में श्रम आयुक्त उनके साथ मिलकर काम करेंगे।

सरकर प्रवास और श्रमिकों के प्रारूप की जानकारी भी पता करने की कोशिश करेगी और उनसे उनके पिछले निवास स्थान और मूल निवास के बारे में पूछा जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के लिए आपात उपायों की घोषणा करने की दिशा में ये जानकारियां महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। कम समय के अंदर प्रवासी श्रमिकों का ब्योरा जुटाना सरकार के लिए चुनौती भरा होगा, ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारी के साथ ही श्रम कल्याण आयुक्त भी कुछ राज्यों में मदद करेंगे।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि डेटाबेस उपलब्ध होने से केंद्र सरकार को राहत शिविरों में रह रहे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था करने और अगर वे चाहें तो उन्हें काम के लिए शहर लाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन यह विचार अभी शुरुआती स्तर पर है और लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय के बाद ही इस दिशा में विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि अगर आश्रय स्थलों रहने वाले लोग कोरोना संक्रमित हों तो उसके लिए आपात उपाय के लिए भी सरकार तैयारी करना चाहती है।

अंजलि भारद्वाज और हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल जवाब के मुताबिक केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार देश भर में करीब 10.3 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि इसमें आश्रय स्थलों को शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में करीब 610 आश्रय शिविर हैं लेकिन केंद्र ने केवल 102 शिविरों से संबंधित ब्योरा ही जमा कराए हैं। इसके अलावा देश भर में तकरीबन 15 लाख श्रमिकों के लिए उनके नियोक्ता ने रहने का प्रबंध किया है। भारद्वाज ने कहा, 'असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो हमारे कुल श्रमबल का करीब 90 फीसदी हैं, उन्हें विषम स्थिति में छोड़ दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण कारोबार ठन होने से उनकी आय का स्रोत खत्म हो गया है। उनकी बचत काफी कम है और कंपनियां मदद के लिए आगे नहीं आ रही हैं क्योंकि उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी देकर सरकार को उन्हें मदद करनी चाहिए।' 21 दिन का लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था, जिसकी वजह से देश भर के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का अपने गांव-घर की ओर जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था क्योंकि उद्योग-धंधे बंद होने से उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। आधिकारिक अनुमान के अनुसार करीब 5 से 6 लाख श्रमिक पैदल ही अपने गांव-घर लौट गए क्योंकि सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी भी लाखों प्रवासी श्रमिक विभिन्न राज्य सरकारों के आश्रय स्थलों में रह रहे हैं।

कोरोना के मामले बढ़कर 5,865 हुए

देश में गुरुवार को कोरोनावायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 169 हो गई। वहीं संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 5,865 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। इन 20 मृतकों में महाराष्ट्र के आठ, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन-तीन, जम्मू-कश्मीर में दो और पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।

वैश्विक स्थिति

- इटली में कोरोनावायरस से 100 डॉक्टरों की मौत
- नेपाल ने दो दिन के लिए लॉकडाउन हटाया
- दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 89,000 से ऊपर, जबकि बीमारों की संख्या 15 लाख के पार
- ट्रंप ने मोदी का शुक्रिया अदा किया, मोदी ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबका देंगे साथ

महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण अब तक सबसे अधिक 72 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में 16-16 लोगों और दिल्ली में नौ लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,346 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। वहीं यह आंकड़ा तमिलनाडु में 834 और दिल्ली में 669 पर पहुंच चुका है। अन्य राज्यों में तेलंगाना में 442, उत्तर प्रदेश में 410 और राजस्थान में कुल 338 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 348 और केरल में 345 मामले हो चुके हैं।

पुराने धारावाहिकों के बल पर दूरदर्शन बना अव्वल

विवेट सुजन पिंटो

लॉकडाउन के दौरान लोकप्रिय पुराने शो के प्रसारण से दूरदर्शन को तगड़ा फायदा मिला है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 28 मार्च से 3 अप्रैल तक लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में डीडी नैशनल सबसे अधिक देखा जाने वाला चैनल बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री के वीडियो संबोधन का 3 अप्रैल को प्रसारण दूरदर्शन और अन्य समाचार चैनलों पर हुआ था, जिसे बड़ी तादाद में दर्शक मिले। उस दिन सुबह 9 बजे सभी चैनलों पर 11.9 करोड़ लोगों ने उस संबोधन को देखा। इससे पहले मोदी की 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा को 19.7 करोड़ लोगों ने देखा था।

बार्क इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी सुनील लुल्ला ने कहा कि डीडी नैशनल पर रामायण, महाभारत, श्रीमान श्रीमति और ब्योमकेश बक्शी जैसे कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया गया है, जिससे आलोच्य सप्ताह के दौरान दर्शकों की संख्या बढ़ी।

समीक्षाधीन अवधि में डीडी नैशनल पर सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक दर्शक इंप्रेशन बढ़कर 58 करोड़ हो गए, जो कोरोनावायरस फैलने से पहले के सप्ताहों में 30 लाख थे। उन्होंने कहा कि शाम के स्लॉट (रात 9 बजे से 10.30 बजे तक) में रिपीट शो ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस समय दर्शक इंप्रेशन 83.5 करोड़ रहे, जो महामारी फैलने से पहले के सप्ताहों में 60 लाख थे। दर्शकों ने पुराने शो के अलावा फिल्म और समाचारों को हाथों हाथ लिया।